

करेंट अफेयर्स

राजस्थान

(संग्रह)



अक्तूबर 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान.....	4
● राजस्थान वरिष्ठ नागरिक अनुकूल राज्य बनेगा.....	4
● धोखाधड़ी के मामलों में जयपुर अग्रणी.....	5
● आपणी बस-राजस्थान रोडवेज पहल.....	6
● राजस्थान का पहला नमो जैवविविधता पार्क.....	7
● राजस्थान में सहकारी समितियों में वृद्धि.....	8
● राजस्थान में गौशाला सब्सिडी में वृद्धि.....	10
● राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य.....	11
● राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास.....	11
● अभ्यास इंद्र-2025.....	12
● राजस्थान ने नया भूमि कानून अधिसूचित किया.....	14
● राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू.....	15
● उदयपुर ने AI-संचालित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया.....	16
● राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक.....	17
● सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर.....	18
● विकसित राजस्थान @2047 विज्ञान डॉक्यूमेंट का अनावरण किया.....	19
● राजस्थान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य.....	20
● राजस्थान में दो प्रमुख श्रम सुधारों की स्वीकृति.....	21
● राजस्थान में घूमर महोत्सव का आयोजन.....	21
● राजस्थान में स्वर्ण भंडार की खोज.....	22
● राजस्थान में FCM पिक ड्राइव.....	23
● राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा.....	25
● पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री पर GST.....	25
राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स.....	27
● अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस.....	27
● राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025.....	28

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च	30
श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती	30
विश्व कपास दिवस 2025	32
विश्व पर्यावास दिवस	33
93वाँ वायुसेना दिवस	33
70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025	34
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	35
विश्व मानक दिवस	36
भारत-दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास (IN-RoKN)	37
विश्व खाद्य दिवस 2025	38
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती	39
विशाखापत्तनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब	40
समुद्र शक्ति का पाँचवाँ संस्करण	41
संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025	42
पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त	43
नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि	45
अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस और '23for23' पहल	46
वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025	48
पूर्वी तिमोर आसियान का 11वाँ सदस्य बना	49
भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर को विज्ञान रत्न	52
त्रिशूल अभ्यास	54
मोंथा चक्रवात	55
DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन	55
8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें स्वीकृत	56
न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त	57
राष्ट्रीय एकता दिवस	58

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान

राजस्थान वरिष्ठ नागरिक अनुकूल राज्य बनेगा

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने **अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस** (1 अक्तूबर) पर अपने संबोधन में राजस्थान को “वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल राज्य” बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य बिंदु

राजस्थान सरकार की पहल:

❖ योगदान का सम्मान:

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं। 1 अक्तूबर को वरिष्ठ नागरिक के कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया।
- राजस्थान में वर्तमान में 63 वृद्धाश्रम संचालित हैं, जो निराश्रित नागरिकों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आश्रय प्रदान करते हैं।
- श्रवण कुमार कल्याण आश्रम जैसी सुविधाएँ वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सहायता, वयस्क शिक्षा, धार्मिक गतिविधियाँ और मनोरंजन उपलब्ध कराती हैं।

❖ समावेशी कल्याण परियोजनाएँ:

- सभी नई कल्याण और अवसंरचना (infrastructure) परियोजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष प्रावधान शामिल किये जाएंगे।

❖ आवास योजनाएँ:

- नई आवासीय परियोजनाओं में रैंप, सहायक सीढ़ियाँ, पार्क और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल होंगी ताकि वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

❖ माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007:

- इस अधिनियम (Act) को सख्ती से लागू किया जा रहा है और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये उपखंड तथा जिला स्तर पर न्यायाधिकरण (tribunals) स्थापित किये गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (International Day of Older Persons):

- यह दिवस वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किये गए योगदान को मान्यता देने और समावेशी तथा वरिष्ठ नागरिक-अनुकूल समाज की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 अक्तूबर, 1990 को नामित किया था। यह वृद्धावस्था पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्ययोजना (1982) और वृद्ध व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र सिद्धांतों पर आधारित है।
- विषय: वर्ष 2025 का विषय “स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ नागरिक: हमारी आकांक्षाएँ, हमारा कल्याण तथा हमारे अधिकार” है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- यह विषय लचीले (resilient) और समानतापूर्ण (equitable) समाज के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- ♦ प्रतिबद्धताएँ एवं वैश्विक ढाँचा:
 - यह पहल संयुक्त राष्ट्र का स्वस्थ आयु दशक (2021-30) अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण पर सतत विकास लक्ष्य 3 के अनुरूप है।
- ♦ भारत ने राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (National Policy on Older Persons – NPOP), 1999 तैयार की।
- ♦ भारत मैट्रिड अंतर्राष्ट्रीय वृद्धावस्था कार्ययोजना (2002) का हस्ताक्षरकर्ता है।
- ♦ दिसंबर 2023 तक भारत में 15.3 करोड़ वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे ऊपर) थे।
- ♦ अनुमान है कि वर्ष 2050 तक यह संख्या बढ़कर 34.7 करोड़ हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 20.8% होगी।

धोखाधड़ी के मामलों में जयपुर अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, हत्या, चोरी, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में जयपुर देश में तीसरे स्थान पर है।

- ♦ हालाँकि, शहर की पुलिस के लिये सबसे बड़ी चिंता धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि है, जिसमें जयपुर देश भर में पहले स्थान पर है।

मुख्य बिंदु

जयपुर में अपराध की स्थिति (NCRB 2023)

- ♦ **धोखाधड़ी:**
 - NCRB के अनुसार, वर्ष 2023 में जयपुर में धोखाधड़ी के 3,331 मामले दर्ज किये गए, जो देश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद बंगलूरु में 3,109, नई दिल्ली में 2,766 और मुंबई में 2,445 मामले दर्ज हुए।
 - इनमें से बड़ी संख्या वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है, जैसे कि नकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग।
 - पुलिस का मानना है कि यह गंभीर चुनौती है क्योंकि इसमें बैंक और वित्तीय सेवा कंपनियों जैसे कई पक्षकार शामिल होते हैं।
- ♦ **चोरी:**
 - चोरी के मामले में जयपुर तीसरे स्थान पर है, जिसमें 10,003 मामले दर्ज हुए। इसके बाद बंगलूरु 10,438 मामलों के साथ और नई दिल्ली 2,28,173 मामलों के साथ पहले तथा दूसरे स्थान पर हैं।
- ♦ **अपहरण:**
 - अपहरण के मामलों में भी समान प्रवृत्ति देखी गई, जहाँ जयपुर में 939 मामले दर्ज हुए, जो बंगलूरु (1,203 मामले) और नई दिल्ली (5,867 मामले) के बाद तीसरे स्थान पर है।
- ♦ **हत्या:**
 - हत्याओं के मामले में जयपुर 131 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि बंगलूरु में 215 और नई दिल्ली में वर्ष 2023 में 521 मामले दर्ज किये गए।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ महिलाओं के खिलाफ अपराध:

- ❶ महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी जयपुर प्रमुखता से शामिल है, विशेषकर महिलाओं की गरिमा भंग करने से संबंधित मामलों में। वर्ष 2023 में जयपुर में 408 मामले दर्ज हुए, जबकि बंगलूरु में 736, मुंबई में 781 और नई दिल्ली में 800 मामले दर्ज हुए।

राजस्थान में कानून और व्यवस्था संबंधी पहल:

- ❖ 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' के अंतर्गत निगरानी एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
- ❖ सरदार पटेल साइबर कंट्रोल सेंटर और वार रूम की स्थापना पर 350 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ❖ विचाराधीन कैदियों की पेशी के लिये 400 वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC) नोड्स की स्थापना।
- ❖ सात केंद्रीय जेलों में अवैध मोबाइल सिग्नल को ब्लॉक करने के लिये T-HCBS सिस्टम की स्थापना।
- ❖ आठ नए साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना का प्रावधान।

आपणी बस-राजस्थान रोडवेज़ पहल

चर्चा में क्यों ?

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्तूबर, 2025 को 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज़' पहल का उद्घाटन किया, जो राजस्थान में ग्रामीण परिवहन संपर्क और यात्री सुविधाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

मुख्य बिंदु



❖ परिचय:

- ❶ यह पहल राज्य बजट की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत परिवहन अवसंरचना को विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में मजबूत बनाया जा रहा है।
- ❶ इससे पहले, इन मार्गों को 'सार्वजनिक परिवहन सेवा' के तहत संचालित किया जाता था, जिसे अब अधिक दृश्यता और एकीकरण के लिये 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज़' के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- इन बसों का संचालन **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC)** की देखरेख में निजी संचालकों द्वारा किया जाएगा, जिससे व्यावसायिक सेवा-प्रदाय एवं रखरखाव मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।

❖ विस्तार:

- यह सेवा ग्रामीण और छोटे शहरों के लिये शुलभ, सुरक्षित तथा विश्वसनीय परिवहन सुनिश्चित करते हुए सशक्त ग्रामीण कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिये 169 ग्राम पंचायतों में संचालित होगी।

❖ परिचालन ढाँचा:

- यह मॉडल राजस्व-साझेदारी व्यवस्था पर आधारित है, जिसके अंतर्गत निजी संचालक राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) को 5-7 रुपये प्रति किमी. का भुगतान करते हैं, जबकि यात्रियों से 1.5 रुपये प्रति किमी. का निश्चित किराया लिया जाता है।
- महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सरकार प्रायोजित लाभार्थियों के लिये मुफ्त यात्रा रियायतें पूर्ववत् जारी रहेंगी।
- सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाए रखने के लिये सभी बसों में **GPS**, पैनिक बटन तथा रीयल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

❖ महत्व:

- यह पहल ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ बनाते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और बाज़ारों तक पहुँच में सुधार करती है, स्थानीय रोज़गार सृजन को बढ़ावा देती है, **डिजिटल सुशासन** को स्मार्ट ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ती है तथा बेहतर सुरक्षा एवं खानपान-सुविधाओं के माध्यम से यात्रियों के विश्वास व सुविधा स्तर को बढ़ाती है।

राजस्थान का पहला नमो जैवविविधता पार्क

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रताप बाण बांध, अलवर में राजस्थान के पहले '**नमो जैवविविधता पार्क**', जिसे 'नमो वन' के नाम से भी जाना जाता है, का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



❖ नमो वन के बारे में:

- ❶ नमो वन एक नई पर्यावरण-अनुकूल पार्क पहल है, जिसे प्रमुख भारतीय शहरों में शुरू किया गया है, जो हरित क्षेत्रों में वृद्धि और शहरी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** के राष्ट्रव्यापी प्रयासों का हिस्सा है।

❖ हरित अवसंरचना:

- ❶ इस पार्क को अलवर के लिये एक हरित फेफड़ा के रूप में देखा जा रहा है, जो स्थानीय हरियाली को बढ़ाएगा और वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा।

❖ जन-जागरूकता:

- ❶ इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना है।

❖ सामुदायिक भागीदारी:

- ❶ यह पहल संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित की गई है, जो भारत की जलवायु कार्रवाई और **जैवविविधता** लक्ष्यों के अनुरूप है।

❖ सतत विकास पर केंद्रित:

- ❶ यह पहल राजस्थान के हरित विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास है और **पर्यावरणीय सतत विकास** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

❖ महत्त्व:

- ❶ यह पार्क शहरी पारिस्थितिकी नियोजन को सार्वजनिक भागीदारी के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्ययोजना** और मिशन LIFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) पहल के तहत भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

राजस्थान में सहकारी समितियों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

सहकार सदस्यता अभियान के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने **सहकारी समितियों** की संख्या में 10% वृद्धि करने की घोषणा की, जिससे ग्रामीण समृद्धि और **समावेशी विकास** में सहकारिता की भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया।

मुख्य बिंदु

❖ सहकार सदस्यता अभियान:

- ❶ 2 से 15 अक्तूबर, 2025 के बीच आयोजित इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में **सहकारी आंदोलन** का विस्तार करना है।

❖ PACS विस्तार:

- ❶ ऐसी 2,158 ग्राम पंचायतों में नई **प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)** स्थापित की जाएंगी, जहाँ वर्तमान में एक भी PACS नहीं है। जिन सहकारी समितियों के पास गोदाम के लिये जगह नहीं है, उन्हें भूमि आवंटित की जाएगी।

❖ किसान सशक्तीकरण:

- ❶ 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त फसल ऋण प्रदान किये गए।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- 2.48 लाख नए किसान 433 करोड़ रुपये के नवीन ऋण से लाभान्वित हुए, जबकि 30,000 लाभार्थियों ने 260 करोड़ रुपये के आजीविका ऋण का लाभ उठाया।

❖ सहायता योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 7,054 करोड़ रुपये प्रदान किये गए।
- राज्य सरकार **मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के तहत प्रति किसान को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रदान करती है।

❖ पशुपालन एवं डेयरी:

- गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत डेयरी गतिविधियों के लिये 1 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध है।
- पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिये मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ विकसित की जा रही हैं।

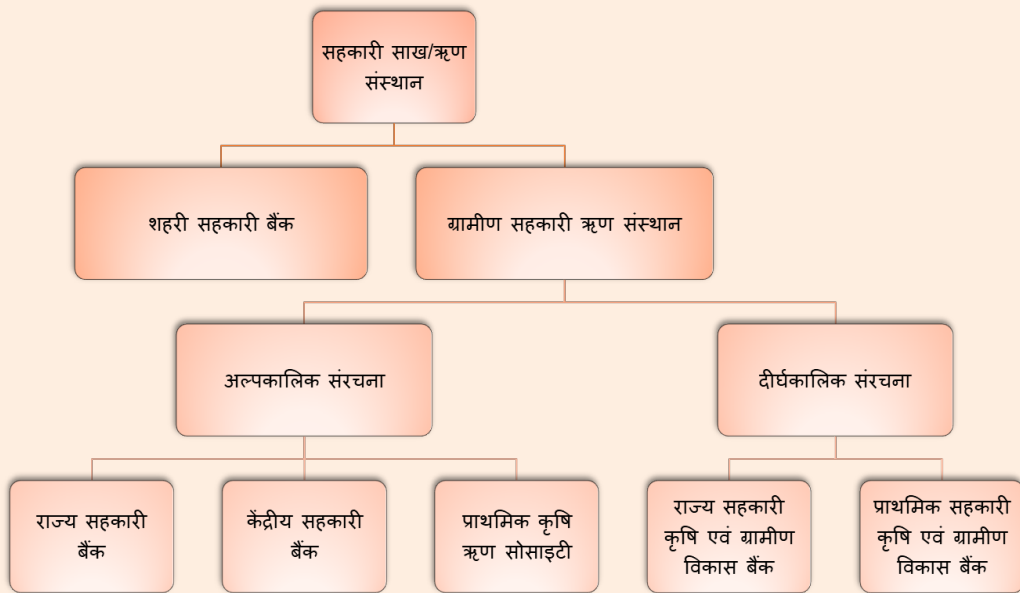
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

❖ PACS के बारे में:

- PACS ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण संस्थाएँ हैं, जो राज्य सहकारी बैंकों (SCB) और ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के अंतर्गत भारत की त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना का आधार बनाती हैं।
- ये किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। पहली PACS वर्ष 1904 में स्थापित हुई थी।
- PACS बैंक नहीं हैं, क्योंकि ये सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 के तहत समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।

❖ स्थिति:

- RBI** (दिसंबर 2022) के अनुसार, भारत में लगभग 1.02 लाख PACS हैं, हालाँकि मार्च 2021 तक केवल 47,297 ही लाभकारी थीं।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान में गौशाला सब्सिडी में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के **मुख्यमंत्री** ने गौ संरक्षण और पारंपरिक कृषि के लिये उपायों की घोषणा की, जिसमें गौशालाओं के लिये सब्सिडी में वृद्धि तथा बैलों का उपयोग करने वाले किसानों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं, जो सतत कृषि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

मुख्य बिंदु

गौशाला सब्सिडी में वृद्धि:

- पंजीकृत गौशालाओं के लिये दैनिक सहायता राशि बढ़ाकर 50 रुपये प्रति गाय और 25 रुपये प्रति बछड़ा कर दी गई है, जिससे पशुधन कल्याण प्रयासों को सशक्त बनाया गया है।

किसान प्रोत्साहन:

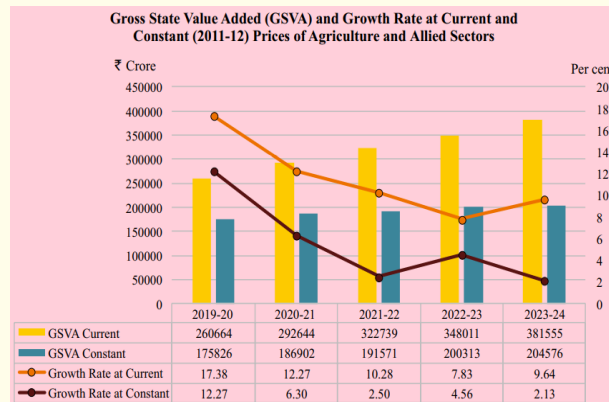
- राजस्थान **बजट** 2025-26 में पारंपरिक बैल-आधारित कृषि करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिये वार्षिक 30,000 रुपये का प्रावधान किया गया है।

धार्मिक पर्यटन विकास:

- राज्य ने खाटूश्यामजी मंदिर और पुंछरी का लोठा जैसे स्थलों के लिये बजटीय आवंटन किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक विरासत पुनरुज्जीवन दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- आध्यात्मिक पर्यटन** को बढ़ावा देने के लिये इस परियोजना के अंतर्गत भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े स्थलों का विकास किया जा रहा है।

नोट:

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का राजस्थान के **सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA)** में योगदान 26.72% रहा, जो 2011-12 में 28.56% था।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में फसलों का हिस्सा 44.53%, पशुधन का 48.58%, **वानिकी** तथा लॉगिंग का योगदान 6.40% एवं **मत्स्य पालन** का योगदान लगभग 0.49% रहा।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान अब आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **जैसलमेर में विस्तार योजनाएँ:**
 - ⦿ रेगिस्तानी ज़िले **जैसलमेर** में वर्ष 2026 से 2029 के बीच छः नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के साथ यह क्षेत्र एक प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।
 - ⦿ ऐतिहासिक रूप से अपनी पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था के लिये प्रसिद्ध जैसलमेर ने विगत 15 वर्षों में **सौर तथा पवन ऊर्जा** परियोजनाओं में बड़े निवेश आकर्षित किये हैं। अब सीमेंट निर्माण के जुड़ने से ज़िले के औद्योगिक आधार में और विविधता आएगी।
- ♦ **निवेश अवलोकन:**
 - ⦿ इन संयंत्रों में 17,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। इनसे राजस्थान की वर्तमान सीमेंट उत्पादन क्षमता में 16 मिलियन टन की वृद्धि होने की संभावना है।
- ♦ **वर्तमान स्थिति:**
 - ⦿ वर्तमान में **आंध्र प्रदेश** 62.5 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ अग्रणी राज्य है, जबकि **राजस्थान** 55 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर है।
 - ⦿ वर्तमान में, **चित्तौड़गढ़** राजस्थान का अग्रणी सीमेंट उत्पादक है, जहाँ देश के कुछ सबसे बड़े सीमेंट निर्माताओं के प्रमुख संयंत्र स्थित हैं।
 - ⦿ इसके अतिरिक्त **नागौर ज़िले** में भी नए सीमेंट संयंत्रों का निर्माण हो रहा है, जिससे राजस्थान के सीमेंट उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।
- ♦ **चूना पत्थर भंडार:**
 - ⦿ राजस्थान में 2.5 अरब टन चूना पत्थर भंडार है, जो भारत के कुल प्रमाणित चूना पत्थर भंडार का लगभग 26% है।
 - ⦿ यही कारण है कि राज्य **सीमेंट उत्पादन** के लिये एक आदर्श स्थान माना जाता है।
 - ⦿ राजस्थान की प्रमुख उत्तरी तथा पश्चिमी बाज़ारों से निकटता तथा मजबूत परिवहन अवसंरचना राज्य में सीमेंट उद्योग की व्यवहार्यता को और सुदृढ़ करती है।

राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान शिक्षा विभाग ने छात्रों में **आधारभूत साक्षरता** को सुदृढ़ करने और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक चार-भागीय कार्ययोजना तैयार की है।

- ♦ प्रस्तावित कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान को **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के कार्यान्वयन में एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, बच्चों की कौशल क्षमता में सुधार करना और राष्ट्रीय शैक्षिक रैंकिंग में नेतृत्व करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

छात्रों का उत्थान:

- **डिजिटल निगरानी:** छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से निगरानी में रखा जाएगा, ताकि निरंतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- **पाठ्यपुस्तक वितरण:** पाठ्यपुस्तकों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, आदर्श रूप से शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के एक महीने के भीतर।
- **भावनात्मक सशक्तीकरण:** सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा पर विशेष वीडियो सेमिनार आयोजित किये जाएँगे, साथ ही छात्रों को तनाव तथा भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने के लिये **परामर्श शिविर (Counseling Camps)** भी आयोजित किये जाएँगे।
- **बोर्ड परीक्षा समर्थन:** बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को दो क्वेश्चन बैंक या मूल्यांकन सामग्री प्रदान की जाएगी, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा **ऑन-कॉल सहायता** भी दी जाएगी।
- **प्रतियोगी परीक्षा तैयारी:** माध्यमिक कक्षाओं के उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी या प्रतियोगी परीक्षा सामग्री खरीदने के लिये **प्रतिपूर्ति** दी जाएगी।

विद्यालय विकास:

- **विद्यालय श्रेणीकरण:** छात्रों के परीक्षा परिणाम, शैक्षणिक प्रदर्शन और खेल उपलब्धियों के आधार पर विद्यालयों को **स्वर्ण (Gold)**, **रजत (Silver)** तथा **कांस्य (Bronze)** श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।
- **स्वर्ण विद्यालय:** उच्च प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को **संसाधन आवंटन में प्राथमिकता** दी जाएगी।

शिक्षक सशक्तीकरण:

- **शिक्षक स्थानांतरण नीति:** नई शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण को छात्रों के प्रदर्शन और अन्य मानकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि दक्ष शिक्षक उन विद्यालयों में नियुक्त हों जहाँ वे अधिकतम प्रभाव डाल सकें।
- **विशिष्ट शिक्षक चयन:** उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम वाले शिक्षकों का चयन **राज्य स्तरीय विशेष संस्थानों** के लिये किया जाएगा, जिससे **संस्थागत स्तर** पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

अभिभावक सहभागिता:

- **मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठकें:** पूरे राज्य में मासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से जोड़ा जा सके और वे अपने बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

अभ्यास इंड्र-2025

चर्चा में क्यों ?

भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'इंड्र-2025' का आयोजन 6 से 15 अक्तूबर, 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर (राजस्थान) में किया जा रहा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





मुख्य बिंदु

- ❖ **उद्देश्य:** इस वर्ष के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य **आतंकवाद-रोधी** अभियानों पर जोर देना है। यह भारत और रूस दोनों की सामरिक नीतियों के अनुरूप है तथा **आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों** से निपटने में उनकी साझा प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
- ❖ **मुख्य क्षेत्र:**
 - ☉ संयुक्त सामरिक अभ्यास
 - ☉ लाइव-फायर ट्रेनिंग
 - ☉ मरुस्थलीय परिस्थितियों में निकट-क्षेत्रीय युद्ध अभ्यास
 - ☉ **बंधक-मुक्ति अभियानों**, उग्रवादी नेटवर्कों के उन्मूलन तथा सुदृढ़ ठिकानों पर सटीक प्रहार की सिमुलेटेड (काल्पनिक) मिशन गतिविधियाँ
- ❖ **विशेषताएँ:**
 - ☉ इस अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले सैन्य अभ्यास (High-intensity Drills) शामिल हैं, जिनमें **मानवरहित हवाई वाहनों (UAV)** के उपयोग से टोही (Reconnaissance) और लक्ष्य निर्धारण (target acquisition) का समन्वय किया जाएगा।
 - ☉ वायु समर्थन (Air Support) समन्वय और सीमित दृश्यता वाले वातावरण में तोपखाने और बख्तरबंद तत्वों (Artillery and Armoured Elements) का समन्वय भी अभ्यास के प्रमुख घटक हैं।
 - ☉ सैनिक कठोर सहभागिता नियमों (Strict Rules of Engagement) के अंतर्गत कार्य करेंगे, ताकि अभियानों का निष्पादन यथार्थपूर्ण और अनुशासित ढंग से हो सके।
- ❖ **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
 - ☉ 'इंद्र' श्रृंखला के सैन्य अभ्यासों की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और इसका आयोजन भारत और रूस में क्रमशः किया जाता है।
 - ☉ इसका अंतिम आयोजन वर्ष 2021 में हुआ था, परंतु वर्ष 2022 में **रूस-यूक्रेन युद्ध** शुरू होने के बाद यह श्रृंखला अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **महत्त्व:** तेजी से विकसित होती सैन्य तकनीकों और संयुक्त अभियानों के संदर्भ में यह अभ्यास दोनों देशों को अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने तथा परस्पर सहयोग और तालमेल (interoperability) को सुदृढ़ करने में सहायता करता है विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में संचालन की क्षमता बढ़ाने हेतु।

राजस्थान ने नया भूमि कानून अधिसूचित किया

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमाम्यकरण) अधिनियम, 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम (Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation- RIICO) के अधिकारों का विस्तार करना है ताकि वह औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के प्रबंधन एवं नियमन को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सके।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** यह अधिनियम, जिसे 3 अक्टूबर, 2025 को **राज्यपाल** की स्वीकृति मिली, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है।
 - ⦿ यह भूमि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने, पूर्व के लेन-देन को मान्य करने और राज्य भर में औद्योगिक विकास को तेज करने का लक्ष्य रखता है।
- ❖ **पृष्ठभूमि:** अधिनियम अप्रैल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के राज्य सरकार बनाम अराफात पेट्रोकेमिकल्स के मामले में दिये गए निर्णय से उत्पन्न समस्याओं को संबोधित करता है।
 - ⦿ निर्णय ने वर्ष 1979 से पहले हस्तांतरित 37 औद्योगिक क्षेत्रों पर RIICO के अधिकार हटा दिये, जिससे इन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों के लिये भूमि प्रबंधन और विकास असंगत हो गया।
 - ⦿ इन चुनौतियों के समाधान के लिये, राज्य राजस्व विभाग ने वर्ष 2025 के बजट सत्र में विधेयक विधानसभा में पेश किया। विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के बाद, यह विधेयक एक चयन समिति को भेजा गया और पारित होने के लिये मंजूर किया गया।
- ❖ **RIICO के अधिकारों में वृद्धि:** अधिनियम औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन, योजना, विकास, रूपांतरण और निपटान के लिये RIICO को पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
 - ⦿ यह RIICO को औद्योगिक क्षेत्र विकास की मुख्य एजेंसी के रूप में मान्यता देता है और इसके कदमों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिन्हें RIICO दशकों से चला रहा है।
- ❖ **पूर्व लेन-देन की वैधता:** यह अधिनियम RIICO द्वारा किये गए सभी पूर्व भूमि-संबंधित निर्णयों को मान्यता देता है, जिसमें भूमि हस्तांतरण, उप-विभाजन, भूखंडों का विलय, भूमि उपयोग में परिवर्तन और RIICO के नियंत्रण में औद्योगिक क्षेत्रों में नियमितीकरण गतिविधियाँ शामिल हैं।
 - ⦿ अब प्रक्रियात्मक त्रुटियों या औपचारिक अनुमोदनों की कमी वाले कार्य भी राज्य कानून के तहत मान्य माने जाएँगे।
 - ⦿ यह प्रावधान विरोधी न्यायालयीन निर्णयों या तकनीकी कमियों पर भी प्रभावी होगा, जिससे लंबे समय से चल रही कानूनी अस्पष्टताओं का समाधान हो सकेगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ छूट: अधिनियम 18 सितंबर, 1979 से पहले रद्द किये गए औद्योगिक भूमि पट्टों को अपने प्रावधानों से स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
- ❖ औद्योगिक क्षेत्रों के लिये राहत: अधिनियम विशेषकर IT, गोदाम एवं होटल जैसे क्षेत्रों की उद्योगों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।
- ❖ इसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन में कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमेयता प्रदान करके निवेशक विश्वास को बढ़ाना है।

राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने राजस्थान विधानसभा द्वारा सितंबर 2025 में पारित राजस्थान गैरकानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है।

- ❖ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, धर्मांतरण केवल वयस्कों के लिये ही संभव हैं, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना और आशय की सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य है।

मुख्य बिंदु

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- ❖ विवाह के लिये पूर्व सूचना: पुरोहित या धर्मगुरु को अंतर-धार्मिक विवाह संपन्न कराने से कम से कम दो महीने पहले जिला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य है।
- ❖ व्यक्तियों को अपनी शादी से कम से कम तीन महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना आवश्यक है।
- ❖ उल्लंघन पर दंड:
 - ❖ इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर ज़बरन धर्मांतरण के लिये दंड हो सकता है, जिसमें 7 से 14 वर्ष तक की कारावास और 5 लाख रूपए से प्रारंभ होने वाला जुर्माना शामिल है।
 - ❖ संरक्षित समूहों (जैसे महिलाएँ, नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति) के पीड़ितों के मामले में दंड में वृद्धि होगी, जिसमें 20 वर्ष तक की जेल और कम से कम 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
 - ❖ सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में अपराधियों को आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
 - ❖ पुनरावर्ती अपराधियों को आजीवन कारावास और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।
- ❖ न्यायालय संबंधी प्रावधान: कानून के अनुसार, सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती होंगे और सत्र न्यायालय में विचारणीय होंगे।
- ❖ धर्मांतरण के लिये शून्य/अमान्य विवाह: केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किये गए विवाह को शून्य घोषित किया जाएगा और ऐसे विवाहों से पहले या बाद में किये गए धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा।
- ❖ छूट: अपने "पारंपरिक धर्म (Ancestral Religion)" में लौटने वाले व्यक्तियों को कानून के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- ❖ अन्य राज्यों में समान कानून: राजस्थान उन राज्यों में शामिल हो गया है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने ज़बरन धर्मांतरण को रोकने के लिये समान कानून पारित किये हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



धार्मिक विश्वास से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- ❖ अनुच्छेद 25: यह अनुच्छेद **अंतःकरण की स्वतंत्रता** (Freedom of Conscience) और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचारित करने का अधिकार सुनिश्चित करता है, बशर्ते कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप हो।
- ❖ अनुच्छेद 26: यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है, बशर्ते कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप हो।
- ❖ अनुच्छेद 27-30: ये अनुच्छेद धार्मिक प्रथाओं में आर्थिक योगदान करने, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिये शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और संचालित करने की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।

उदयपुर ने AI-संचालित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया

चर्चा में क्यों ?

उदयपुर ने **यातायात प्रबंधन** में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना के तहत व्यस्त फतेहपुरा चौराहे पर **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम** शुरू किया है।

- ❖ इस पहल का लक्ष्य ट्रैफिक के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना, जाम को कम करना और यात्रियों का समय बचाना है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** पारंपरिक ट्रैफिक लाइटों के विपरीत, जो निश्चित समय-सारणी पर काम करती हैं, नई AI-आधारित प्रणाली/सिस्टम में **हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे और सेंसर** लगाए गए हैं, जो वाहनों की रियल-टाइम आवाजाही की निगरानी करते हैं।
 - ⦿ AI प्रणाली प्रत्येक लेन में **यातायात घनत्व का लगातार विश्लेषण** करती है और सिग्नल समय को स्वचालित रूप से समायोजित करती है ताकि ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाया जा सके।
 - ⦿ जिन लेन में **ट्रैफिक कम होता है**, उन्हें **कम समय के लिये ग्रीन सिग्नल** दिया जाता है, जबकि भीड़भाड़ वाली लेन को लंबे समय के लिये **ग्रीन सिग्नल** दिया जाता है ताकि चौराहे पर वाहनों की **सुगम आवाजाही** सुनिश्चित की जा सके।
 - ⦿ यह प्रणाली एक **मोबाइल एप्लिकेशन** से भी जुड़ी हुई है, जिससे ट्रैफिक अधिकारी दूरस्थ रूप से यातायात की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर **डेटा-आधारित समायोजन** कर सकते हैं।
- ❖ **आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता:** सामान्य ट्रैफिक नियंत्रण के अतिरिक्त, इस प्रणाली में **साउंड सेंसर** लगाए गए हैं जो **एंबुलेंस और फायर इंजन की सायरन** को पहचान सकते हैं।
 - ⦿ जब इस प्रकार के सायरन का पता चलता है, तो AI तुरंत संबंधित सिग्नल को **हरा कर देता है**, जिससे आपातकालीन वाहन **बिना किसी विलंब के चौराहे से गुज़र सकते हैं** और यह सुविधा आपात स्थितियों में **प्रतिक्रिया समय को सुधारने** के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है।
- ❖ **डेटा-आधारित शहरी गतिशीलता:** तत्काल जाम प्रबंधन के अतिरिक्त, यह AI प्रणाली पूरे दिन यातायात **डेटा एकत्र और रिकॉर्ड** करती है। यह जानकारी शहर के अधिकारियों को **दीर्घकालिक ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण** करने और अधिक प्रभावी प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करेगी।
- ❖ **महत्व:** यदि फतेहपुरा ट्रायल प्रभावी सिद्ध होता है, तो उदयपुर के अन्य प्रमुख चौराहों पर इसी प्रकार की AI-आधारित प्रणालियों को लागू करने की योजना है। यह स्मार्ट और डेटा-संचालित शहरी गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

पर्यटन मंत्रालय ने 14-15 अक्टूबर, 2025 को उदयपुर में दो दिवसीय राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की।



मुख्य बिंदु

- ♦ **परिचय:** इस कार्यक्रम में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए, ताकि भारत के पर्यटन परिदृश्य को सामूहिक रूप से पुनः आकार दिया जा सके।
- **महत्त्व:** यह बैठक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण “एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य” को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम थी। यह पहल **केंद्रीय बजट 2025-26** में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में कम-से-कम एक वैश्विक मानक का पर्यटन स्थल विकसित करना है, जो विकसित भारत रोडमैप का हिस्सा है।
 - ❏ चयन मानदंड: इसमें पहुँच, मौजूदा बुनियादी ढाँचा, धारण क्षमता और समग्र विकास क्षमता शामिल हैं।
- ♦ **हितधारक परामर्श:** दो दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से दो रणनीतियों पर चर्चा हुई: **गंतव्य विकास (Destination Development)** और **गंतव्य प्रबंधन (Destination Management)**।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने **राष्ट्रीय पर्यटन परिवर्तन एजेंडा** के अनुरूप प्रतिष्ठित गंतव्यों के विकास के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये:
 - ❏ **50 गंतव्य विकास:** निजी क्षेत्र द्वारा संचालित पर्यटन हबों पर ध्यान केंद्रित।
 - ❏ **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (PLI):** गंतव्य प्रबंधन में उच्च मानकों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिये **PLI आधारित डेस्टिनेशन मैच्युरिटी मॉडल** की शुरुआत।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **क्षेत्रीय प्रस्तुतियाँ:** प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ने एक संभावित गंतव्य को वैश्विक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने हेतु प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिये, राजस्थान ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर जैसे गंतव्यों का प्रस्ताव दिया, जिसमें कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे की तैयारियों तथा अनुमानित परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ शामिल थीं।
- ❖ **एकीकृत पर्यटन प्रचार योजना के प्रारूप मार्गदर्शक:** बैठक में एकीकृत पर्यटन प्रचार योजना के प्रारूप मार्गदर्शक पर भी विशेष चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
 - ❶ केंद्र सरकार “डिजिटल और ग्रीन (DG) टूरिज़्म पॉलिसी” भी तैयार कर रही है, जिसमें सभी राज्यों से सुझाव लेकर सतत तथा नवाचारपूर्ण पर्यटन विकास के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया जाएगा।

सांगानेरी प्रिंटेड कंबल कवर

चर्चा में क्यों ?

यात्री सुविधा बढ़ाने और भारतीय पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन कंबलों के लिये सांगानेरी प्रिंटेड कवर पेश करने वाली एक पायलट परियोजना शुरू की।

- ❖ इस कंबल परियोजना के साथ-साथ, मंत्री ने उत्तर-पश्चिम रेलवे जोन के 65 छोटे और मध्यम आकार के स्टेशनों पर अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म तथा यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया, जिसमें कुल निवेश 100 करोड़ रुपये है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** यह पायलट पहल जयपुर के खतिपुरा रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई और यह भारतीय रेलवे में समग्र यात्री अनुभव सुधारने की दिशा में एक कदम है।
- ❖ **कार्यान्वयन:** परियोजना को प्रारंभ में जयपुर-असरावा सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12981) की AC कोचों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
- ❖ **उद्देश्य:** पहल का उद्देश्य धुलाई योग्य प्रिंटेड कंबलों के माध्यम से स्वच्छता और यात्री संतुष्टि को बढ़ाना है, जो घरेलू उपयोग वाले मॉडलों के समान हैं।
- ❖ **डिज़ाइन विचार:** सांगानेरी प्रिंटेड कंबलों को टिकाऊपन, धुलाई में आसानी और लंबे समय तक प्रिंट टिकने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- ❖ **सांस्कृतिक समाकलन:** सांगानेरी प्रिंट के अतिरिक्त, रेलवे विभिन्न राज्यों के पारंपरिक वस्त्र डिज़ाइनों को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है, जिससे रेलवे सेवाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सांगानेरी-प्रिंट

- ❖ **उत्पत्ति और परंपरा:** सांगानेरी राजस्थान के जयपुर जिले का एक छोटा गाँव है, जो सदियों पुरानी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की परंपरा के लिये प्रसिद्ध है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
- ❖ **डिज़ाइन विशेषताएँ:** इस लिये की पहचान जटिल पुष्प आकृतियों और बारीक विवरणों से होती है, जो गहरी कलात्मक विरासत को दर्शाती हैं।
- ❖ **प्रेरणा और सौंदर्यशास्त्र:** सांगानेरी प्रिंट प्रकृति और मुगल वास्तुकला से प्रेरित होते हैं, जिससे सुंदर, सुसंगत एवं समृद्ध पैटर्न वाले डिज़ाइन तैयार होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रंगों के साथ बनाया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने जयपुर में विकसित राजस्थान @2047 विज़न डॉक्यूमेंट का अनावरण किया।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** अगस्त, 2025 में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत, यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य में बदलने के लिये एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप है।
- ❖ यह समावेशी और सतत् विकास पर जोर देता है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों तथा वंचित वर्ग को प्राथमिकता प्रदान की गई है।
- ❖ लक्ष्य 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जिसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के मुख्य स्तंभ होंगे।
- ❖ **थीम्स और फोकस क्षेत्र:** विज़न डॉक्यूमेंट चार प्रमुख थीमों के चारों ओर संरचित है, जो तेरह महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करती हैं:
 - ❖ **सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण:** कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित, ताकि मानव विकास को बढ़ावा दिया जा सके तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित हो।
 - ❖ **तीव्र विकास, समृद्धि और रोज़गार:** उद्योग, खनन, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास पर जोर, ताकि व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजित किया जा सके तथा समावेशी समृद्धि सुनिश्चित हो।
 - ❖ **बुनियादी ढाँचा और सतत् विकास:** जल सुरक्षा, पर्यावरणीय सततता और जलवायु लचीलापन को प्राथमिकता, ताकि पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण तथा जलवायु-सहनीयता (Climate Resilience) बुनियादी ढाँचे का प्रारूप तैयार किया जा सके।
 - ❖ **नीति, वित्त और प्रशासन:** ग्रामीण-शहरी विकास, वित्तीय प्रबंधन और सुशासन को एकीकृत करना, ताकि संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता एवं प्रशासनिक दक्षता को प्रबल किया जा सके।
- ❖ **कार्यान्वयन ढाँचा:**
 - ❖ **विभागीय कार्य योजनाएँ:** प्रत्येक विभाग विज़न लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट योजनाएँ तैयार करेगा।
 - ❖ **वार्षिक मूल्यांकन:** परिणामों को ट्रैक करने के लिये वित्तीय और प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी।
 - ❖ **निरंतर निगरानी:** जवाबदेही और समय पर सुधार सुनिश्चित करने के लिये मूल्यांकन ढाँचे अपनाए जाएंगे।
 - ❖ **महत्वपूर्ण वर्ष:** वर्ष 2030, 2035 और 2040 के लक्ष्य अनुसार प्रगति के मानक निर्धारित किये गए हैं।

वर्ष 2047 तक प्रमुख लक्ष्य

क्षेत्र	लक्ष्य
निर्माण उद्योग	सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (GSVA) में हिस्सा 20% तक बढ़ाना
स्वास्थ्य	जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक बढ़ाना
बाल स्वास्थ्य	शिशु मृत्यु दर को 1,000 जीवित जन्मों पर 10 से कम करना

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



शिक्षा	100% स्कूल नामांकन प्राप्त करना; सभी स्कूलों को स्मार्ट और कंप्यूटर-सक्षम संस्थानों में उन्नत करना
महिला सशक्तीकरण	महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 60% से अधिक बढ़ाना
पर्यटन	घरेलू पर्यटकों में राजस्थान का हिस्सा 15% तक बढ़ाना

राजस्थान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब शिक्षा, संस्कृत शिक्षा तथा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों और कार्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य होगा।

मुख्य बिंदु

- कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु इस निर्णय की घोषणा की।
- दैनिक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत: सभी सरकारी विद्यालयों तथा कार्यालयों में कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से तथा समापन राष्ट्रगीत से किया जाएगा। उपस्थिति को भागीदारी से जोड़ा जाएगा।
- निगरानी और अनुपालन: संस्थानों को प्रतिदिन जियो-टैग्ड फोटो प्रस्तुत कर भागीदारी का सत्यापन करना होगा। एक औपचारिक आदेश में कार्यान्वयन तथा गैर-अनुपालन पर दंड का प्रावधान किया जाएगा।
- एकरूप वर्दी नीति: अगले शैक्षणिक सत्र से सभी विद्यालयों तथा शिक्षकों के लिये एक समान वर्दी लागू की जाएगी। टाई को हटाया जाएगा तथा स्थानीय अधिकारी अनुपालन की निगरानी करेंगे।
- अतिरिक्त सुधार: सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिये पहचान-पत्र अनिवार्य होगा तथा एसएमएस प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति की सूचना अभिभावकों को प्रेषित की जाएगी।
- महत्त्व: यह कदम राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, जवाबदेही और समानता को प्रोत्साहित करता है तथा विद्यालयों एवं कार्यालयों में पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत

- जन-गण-मन (राष्ट्रगान) मूल रूप से रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला में रचित (1911 में) था। इसे हिंदी में भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।
 - इसे पहली बार 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
- भारत का राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था।
 - यह गीत पहली बार वर्ष 1870 में लिखा गया था और बाद में वर्ष 1882 में उनके उपन्यास “आनंदमठ” में सम्मिलित किया गया।
 - इसे पहली बार वर्ष 1896 के INC सत्र में गाया गया था।
 - यह एक देशभक्तिपूर्ण गीत है, जो भारत माता के प्रति श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत था।
- भारत के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान में दो प्रमुख श्रम सुधारों की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और श्रमिक कल्याण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा** ने राजस्थान में **सुरक्षित, गरिमामय तथा प्रगतिशील कार्य वातावरण** को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो प्रमुख **श्रम सुधारों** को स्वीकृति प्रदान की।

मुख्य बिंदु

♦ राजस्थान दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025:

- **बाल श्रम निषेध:** 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर प्रतिबंध है।
- **प्रशिक्षुओं के लिये न्यूनतम आयु** 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है।
- **किशोरों के लिये संरक्षण (14-18 वर्ष):** उनकी **शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा** के लिये रात के समय काम करने पर प्रतिबंध।
- **संशोधित कार्य मानक:** दैनिक कार्य सीमा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है तथा त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा 126 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।

♦ राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम, 2025:

- **महिला रोज़गार प्रावधान:** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर, महिला श्रमिकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने पर अनुमोदित कारखाना वातावरण में काम करने की अनुमति देता है।
- **अनिवार्य सुरक्षा उपाय:** नियोक्ताओं को सुरक्षात्मक उपकरण (मास्क, दस्ताने, श्वासयंत्र) उपलब्ध कराने होंगे, सुरक्षित वायु गुणवत्ता बनाए रखनी होगी तथा सभी कर्मचारियों के लिये नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना होगा।

राजस्थान में घूमर महोत्सव का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान की **उप-मुख्यमंत्री**, **दिया कुमारी**, ने घोषणा की है कि राज्य सरकार नवंबर में राजस्थान के पारंपरिक शाही नृत्य रूप को मनाने और प्रचारित करने के लिये सातों संभागीय मुख्यालयों में **घूमर उत्सव** का आयोजन करेगी।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

आयोजन:

- पर्यटन विभाग 19 नवंबर, 2025 को सातों संभागीय मुख्यालयों- जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में एक साथ घूमर उत्सव का आयोजन करेगा।

उद्देश्य:

- राजस्थान के पारंपरिक घूमर नृत्य को पुनर्जीवित और संरक्षित करना।
- सांस्कृतिक एवं पर्यटन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- राजस्थान को एक जीवंत सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रचारित करना।

भागीदारी:

- 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियाँ तथा महिलाएँ व्यक्तिगत या समूह में पंजीकरण कर भाग ले सकती हैं, जबकि प्रतियोगिता खंड के लिये केवल 20 से 25 सदस्यों की समूह प्रविष्टियों की अनुमति होगी।

पुरस्कार:

- इस महोत्सव में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे और विजेता समूहों को राज्य के प्रमुख पर्यटन कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

घूमर नृत्य के बारे में:

- घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो ऐतिहासिक रूप से विशेष अवसरों पर शाही महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- इस नृत्य की विशेषता सुंदर गोलाकार चाल, रंग-बिरंगे परिधान और लयबद्ध ताली तथा घुमाना है।
- इसे राजस्थान में नारीत्व, सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राजस्थान में स्वर्ण भंडार की खोज

चर्चा में क्यों?

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा राजस्थान के बाँसवाड़ा ज़िले में नवीन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है।

मुख्य बिंदु

स्वर्ण भंडार के बारे में:

- घाटोल तहसील के कांकरियागढ़ा ब्लॉक में नवीनतम खोज में अनुमानित 1.20 टन स्वर्ण, साथ ही ताँबा, निकल और कोबाल्ट के अंश भी शामिल हैं।
- यह इस क्षेत्र में स्वर्ण की लगातार तीसरी खोज है, जिससे कर्नाटक के बाद बाँसवाड़ा के प्रमुख स्वर्ण खनन केंद्र बनने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।
- सरकार ने खनिज सामग्री, गुणवत्ता, मात्रा और गहराई की पुष्टि के लिये G-2 स्तर की विस्तृत जाँच को स्वीकृत दे दी है, जिसके आधार पर खनन निविदाएँ जारी की जाएंगी तथा वाणिज्यिक निष्कर्षण शुरू किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



♦ **संबद्ध खनिज:**

- स्वर्ण के साथ-साथ, इस क्षेत्र में ताँबा (लगभग 1,000 टन), निकल और कोबाल्ट के भंडार भी हैं, जो बैटरी तथा **नवीकरणीय ऊर्जा** उद्योगों के लिये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

♦ **भू-वैज्ञानिक संदर्भ:**

- बाँसवाड़ा अरावली पर्वतमाला के साथ स्थित है, जहाँ की चट्टानों की आयु अनुमानित रूप से 5,000 वर्ष से अधिक है।
- समय के साथ भू-वैज्ञानिक गतिविधियों ने खनिज-समृद्ध चट्टानों को पृथ्वी की सतह के निकट ला दिया है, जिससे इस क्षेत्र में **स्वर्ण, ताँबा, निकल, कोबाल्ट** और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

♦ **आर्थिक संभावना:**

- निष्कर्षण शुरू हो जाने के बाद, राजस्थान के **कर्नाटक के बाद** स्वर्ण का निष्कर्षण करने वाला दूसरा राज्य बनने की संभावना है, जो संभवतः **भारत के कुल स्वर्ण उत्पादन में 25% से अधिक का योगदान देगा।**
- इस विकास से **स्थानीय रोज़गार में वृद्धि**, नई अवसंरचना का निर्माण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के **सुदृढ़ होने की संभावना है।**

♦ **पूर्व की खोजें:**

- इससे पहले, GSI ने घाटोल तहसील के **भुकिया और जगपुरा क्षेत्रों में 11.48 करोड़ टन स्वर्ण अयस्क की पहचान की थी।** इन स्थलों में **13,739 टन कोबाल्ट तथा 11,146 टन निकल भी पाए गए थे।**

राजस्थान में FCM पिंग ड्राइव

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग राज्य में गर्भवती महिलाओं में **एनीमिया** से निपटने के लिये फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज (FCM) इंजेक्शन के उपयोग की तैयारी कर रहा है।

मुख्य बिंदु

♦ **पिंग ड्राइव के बारे में:**

- राजस्थान स्वास्थ्य विभाग **मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण एनीमिया से निपटने के लिये 17 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक FCM पिंग ड्राइव अभियान शुरू करेगा।**
- इस पहल का उद्देश्य **फेरिक कार्बोक्सिमाल्टोज (FCM) इंजेक्शन के उपयोग को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी** लाना है, जो **आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के निदान और उपचार में प्रभावी है।**
- FCM इंजेक्शन, जैसे कि ओरोफर FCM, शरीर में आयरन स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, **लाल रक्त कोशिका निर्माण और हीमोग्लोबिन को बढ़ावा देते हैं, जो ऑक्सीजन परिवहन के लिये आवश्यक हैं तथा गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं को रोकते हैं।**

♦ **डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ:**

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित यादव ने FCM पिंग ड्राइव की शुरुआत की और FCM उपयोग दिशानिर्देश, पोस्टर तथा डिजिटल गर्भ सूत्र ऐप्लिकेशन प्रस्तुत किया, जो सेवा प्रदाताओं के लिये **सही खुराक की गणना करता है।**
- ये डिजिटल उपकरण **क्षमता निर्माण, वास्तविक समय निगरानी और डेटा-आधारित निर्णय लेने को सुधारने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जिससे बेहतर सेवा वितरण तथा मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार सुनिश्चित हो सके।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



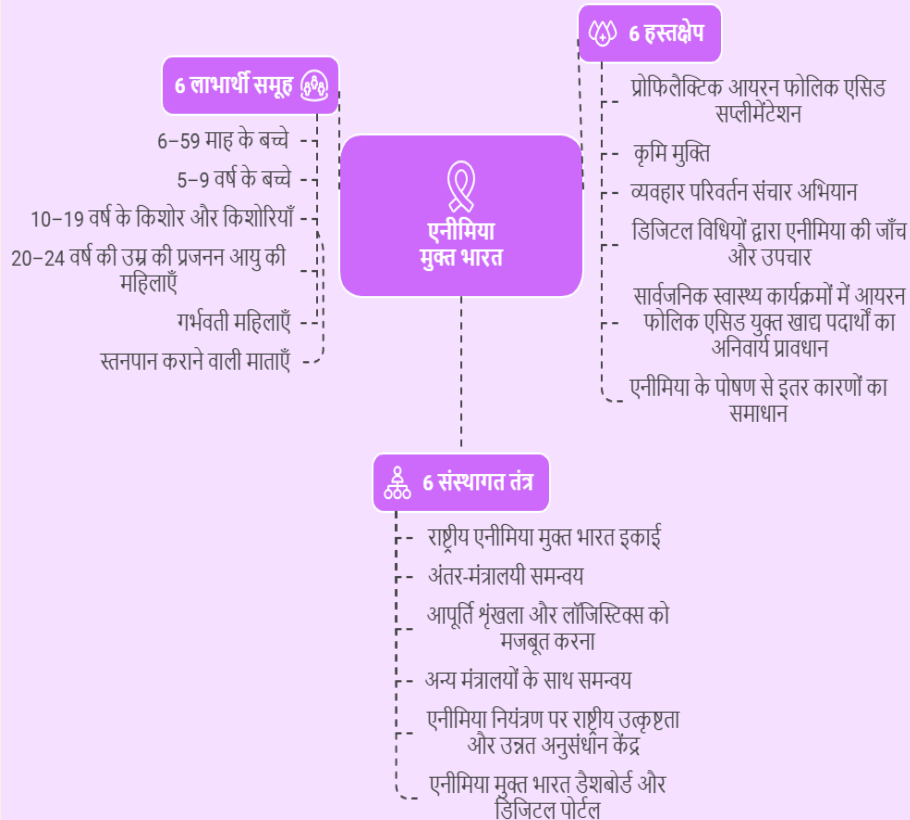
सहयोग:

- स्वास्थ्य विभाग ने विकास साझेदार Jhpiego के साथ मिलकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन हेतु FCM के प्रभावी उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करना था।

एनीमिया

- एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जो मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है और अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है।
- इसका प्रभाव थकान, कमजोरी और शारीरिक तथा संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में कमी के रूप में दिखाई देता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएँ जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम प्रति डेसिलिटर (g/dL) से कम हो और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका हीमोग्लोबिन स्तर 11.0 g/dL से कम हो, उन्हें एनीमिया ग्रसित माना जाता है।

एनीमिया मुक्त भारत: 6x6x6 रणनीति



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राजस्थान के 6 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार ने **स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर** पहल के अंतर्गत राज्य में छह शहरों को विकसित करने हेतु जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (JSCL) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

परियोजना के बारे में:

- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की **स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर** पहल के अनुरूप शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है।
- प्रस्ताव के तहत **मंडावा, खाटू श्यामजी, भिवाड़ी, अलवर, बीकानेर और भरतपुर** को **स्मार्ट सिटी** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इन शहरों के विकास के लिये जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (JSCL) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया गया है।

बजट आवंटन:

- वर्ष 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने अगले तीन वर्षों में 900 करोड़ रुपये के निधि आवंटन के साथ एक दर्जन से अधिक **स्वच्छ एवं हरित पारिस्थितिकी शहरों** के विकास की घोषणा की है। प्रस्तावित शहरों में शामिल हैं:
 - बीकानेर और भरतपुर को 80-80 करोड़ रुपये का बजट अनुदान।
 - मंडावा और खाटू श्यामजी को 30-30 करोड़ रुपये।
 - भिवाड़ी और अलवर का विकास क्रमशः 50 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

स्वच्छ और हरित पारिस्थितिकी शहर पहल

- यह राज्य के पहले 'ग्रीन बजट' के हिस्से के रूप में वर्ष 2025 में प्रारंभ की जाने वाली एक महत्वपूर्ण शहरी स्थिरता पहल है।
- इसका उद्देश्य राजस्थान के 16 चयनित शहरों को एकीकृत पर्यावरणीय, तकनीकी एवं अवसंरचना उन्नयन के माध्यम से आदर्श शहरी केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
- इसमें जलवायु लचीलापन, **हरित ऊर्जा** और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- यह पहल राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के अनुरूप तैयार की गई है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल विस्तार, स्थायी अवसंरचना और जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देना है।
- एक 'ग्रीन फील्ड मॉडल' के तहत प्रत्येक शहर में 3-4 वर्ग किमी के 'लाइट हाउस क्षेत्र' को सड़क, सौर ऊर्जा तथा एकीकृत उपयोगिताओं के उच्च मानकों के साथ विकसित किया जाएगा।

पुष्कर मेले में घोड़ों की बिक्री पर GST

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान राज्य GST विभाग ने व्यापार को औपचारिक बनाने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार **पुष्कर मेले** में घोड़ों की बिक्री पर 5% **GST** लगाया किया है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस

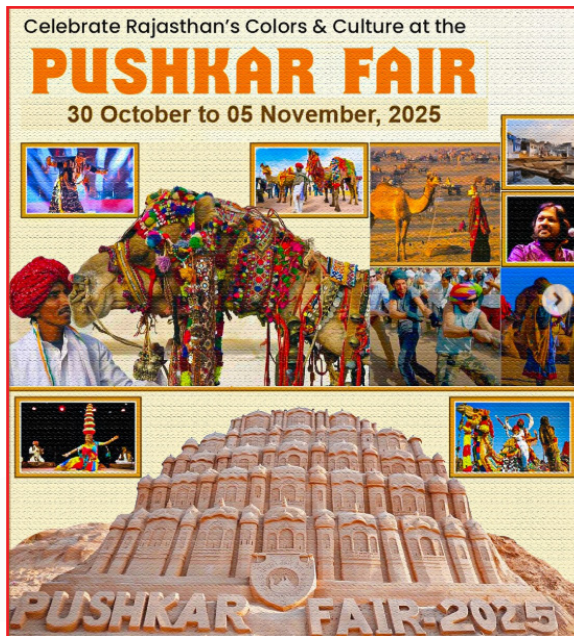


IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





मुख्य बिंदु

कार्यान्वयन:

- पशुपालन विभाग प्रत्येक लेनदेन के लिये रसीद जारी करेगा, जो GST संग्रह का आधार बनेगी।
- अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, घोड़ों के परिवहन की निगरानी और दस्तावेजों के सत्यापन के लिये प्रमुख मार्गों पर जाँच चौकियाँ स्थापित की गई हैं।

पुष्कर मेले के बारे में:

- पुष्कर मेला, जिसे पुष्कर ऊँट मेला के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के पुष्कर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पाँच दिवसीय पशु और सांस्कृतिक उत्सव है, जो आमतौर पर अक्तूबर तथा नवंबर के बीच आयोजित होता है।
- इसे विश्व के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक माना जाता है, जो भारत और विदेश से व्यापारियों तथा आगंतुकों को आकर्षित करता है।
- पशुधन व्यापार के अलावा, यह मेला एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें मटका फोड़, सबसे लंबी मूँछें और दुल्हन प्रतियोगिता जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताएँ शामिल हैं।
- हाल के वर्षों में मेले में आधुनिक आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें स्थानीय पुष्कर क्लब और विदेशी पर्यटकों की टीमों के बीच प्रदर्शनी फुटबॉल मैच शामिल है।
- पुष्कर मेला आज भी एक जीवंत सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बना हुआ है, जो राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात से क्रेताओं एवं किसानों को आकर्षित करता है, साथ ही राजस्थान की समृद्ध घुड़सवारी विरासत व मनुष्यों और घोड़ों के बीच स्थायी बंधन का उत्सव मनाता है।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

चर्चा में क्यों ?

भारत में 2 अक्तूबर को **महात्मा गांधी** के जन्म दिवस के सम्मान में **गांधी जयंती** के रूप में मनाया जाता है।

- इस दिन को **संपूर्ण विश्व** में **अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस** के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को 140 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था, जिससे इसे **सार्वभौमिक महत्त्व** प्राप्त हुआ।

मुख्य बिंदु

महात्मा गांधी के बारे में:

- जन्म:** महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर, 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में हुआ था।
- संक्षिप्त परिचय:** वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के **राष्ट्रवादी आंदोलन** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पुस्तकें:** हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा)
- मृत्यु:** 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
 - 30 जनवरी को **शहीद दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का नेतृत्व:** महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन गए और इन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिये **अहिंसक प्रतिरोध** तथा **जन-आंदोलन** की वकालत की।
 - वर्ष 1924 का **बेलगाम अधिवेशन** कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
- असहयोग आंदोलन (NCM) (1920-22):** गांधीजी ने **जलियाँवाला बाग हत्याकांड** और दमनकारी **रॉलेट एक्ट** की प्रतिक्रिया में NCM की शुरुआत की।
 - उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया।
 - गांधीजी को **बोअर युद्ध** में उनकी भूमिका के लिये वर्ष 1915 में **कैसर-ए-हिंद** उपाधि से सम्मानित किया गया था लेकिन उन्होंने जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष 1920 में इसे वापस कर दिया था।
- दांडी मार्च (1930):** गांधीजी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। इस क्रम में **सविनय अवज्ञा आंदोलन** की शुरुआत हुई।
- भारत छोड़ो आंदोलन (QIM), 1942:** गांधीजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए QIM का आह्वान किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- उनके नारे “करो या मरो” ने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिये प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में तथा अधिक वृद्धि हुई।
- ♦ अहिंसा का दर्शन: अपने पूरे सक्रियता अभियान के दौरान गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वकालत की।
- उनके दृष्टिकोण ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया बल्कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व वाले विश्वव्यापी नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया।

राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों ?

आयुष मंत्रालय ने प्रो. बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूस ई.टी. और वैद्य भावना प्रशर को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये **राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025** से सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु

- ♦ पुरस्कार के बारे में:
 - यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है और पारंपरिक **भारतीय चिकित्सा** में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है।
 - यह आयुर्वेद के प्रचार, संरक्षण और नवाचार में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
 - वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता आयुर्वेद के तीन महत्त्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं- विद्वत्ता, पारंपरिक अभ्यास और वैज्ञानिक नवाचार।
- ♦ विजेता:
 - प्रो. बनवारी लाल गौर आयुर्वेदिक शिक्षा और संस्कृत साहित्य में छह दशकों का योगदान देने वाले विद्वान तथा शिक्षाविद् हैं, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान सहित कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
 - वैद्य नीलकंठन मूस ई.टी. केरल स्थित वैद्यरत्नम समूह के प्रमुख हैं और 200-वर्षीय आयुर्वेदिक परंपरा की आठवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - उन्हें आयुर्वेद को जीवंत और समुदाय-उन्मुख अभ्यास के रूप में संरक्षित तथा आधुनिक बनाने के लिये जाना जाता है।
- ♦ वैद्य भावना प्रशर आयुर्जिनोमिक्स (Ayurgenomics) में अग्रणी हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक प्रकृति अवधारणाओं को आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान से जोड़ा और उनके योगदान को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम में एकीकृत किया गया।
- ♦ महत्त्व:
 - यह पुरस्कार पारंपरिक विद्वत्ता, पारंपरिक अभ्यास और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद की निरंतरता तथा विकास को मान्यता देता है।
 - एकीकृत एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
 - पारंपरिक चिकित्सा और नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



आयुष चिकित्सा पद्धति

आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं, आयुर्वेद का 5000+ वर्षों का प्रलेखित इतिहास है।

आयुर्वेद

- संहिता काल (1000 ईसा पूर्व): परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा
- चरक संहिता: सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता
- सुश्रुत संहिता: आठ विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सीय विधियाँ प्रदान करती है

मुख्य शाखा:

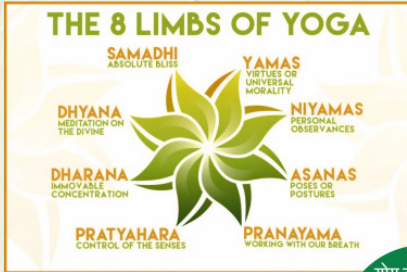
- आत्रेय पुनर्वसु- चिकित्सकों की शाखा
- दिगोदास धन्वतरि - शल्यचिकित्सकों की शाखा

आयुर्वेद की शाखाएँ

- काय चिकित्सा- चिकित्सा।
- शल्य चिकित्सा- सर्जरी।
- शालाक्य तंत्र- ईएनटी और नेत्र विज्ञान।
- बाल रोग चिकित्सा।
- अगद तंत्र- विष विज्ञान।
- भूतविद्या - मनोरोग।
- रसायन- कायाकल्प चिकित्सा और जराचिकित्सा।
- वाजीकरण तंत्र- सेक्सोलॉजी।



योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा



- प्राकृतिक चिकित्सा: 5 प्राकृतिक तत्वों - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की सहायता से उपचार
- शरीर की स्व-उपचार क्षमता सिद्धांतों और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर आधारित
- रोग-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है

योग को सर्वप्रथम महार्षि पतंजलि ने व्यवस्थित रूप में योगसूत्र के रूप में प्रतिपादित किया

यूनानी

ग्रीस में अग्रणी, अरबों द्वारा 7 सिद्धांतों के रूप में विकसित (अमूर-ए-तब्बिया)

- बुकरात (हिप्पोक्रेटस) और जालीनस (गैलेन) की शिक्षाओं के ढाँचे के आधार पर
- चार ह्यूमर्स का हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत अर्थात् रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त
- WHO द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया

सिद्ध

10000 - 4000 ईसा पूर्व; सिद्धर अगस्तिया- सिद्ध चिकित्सा के जनक

- निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पुनर्जीवनात्मक और पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य देखभाल
- 4 घटक: लैट्रो-रसायन विज्ञान, चिकित्सा अभ्यास, योग अभ्यास और बुद्धि
- 3 निदानात्मक ह्यूमर्स (मुक्कुट्रम) और 8 महत्वपूर्ण परीक्षणों (एन्वागई थेरबु) पर आधारित है

आयुर्वेद के 3 गुण (त्रिदोष): वात, पित्त और कफ

सोवा रिग्पा

उत्पत्ति: भगवान बुद्ध के समय 2500 वर्ष पूर्व भारत में

- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि के हिमालयी क्षेत्रों में पारंपरिक चिकित्सा।
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (वर्ष 2010 में संशोधित) द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त।

होम्योपैथी

जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया

- जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया।
- औषधियाँ मुख्यतः प्राकृतिक पदार्थों (पौधे उत्पाद, खनिज, पशु स्रोत) से तैयार की जाती हैं।
- वर्ष 1810 में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा भारत में लाया गया; वर्ष 1948 में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।

3 प्रमुख सिद्धांत:

- सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर ("सम: समम् शमयति" या "समरूपता")
- सिंगल मेडिसिन
- मिनिमम डोज़



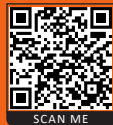
Drishti IAS

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने **माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन** लॉन्च किया, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के नेतृत्व और नागरिक सहभागिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

❖ उन्होंने **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** को **माई भारत पोर्टल** से एकीकृत करने की भी घोषणा की, जिससे देश भर में युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की व्यापक पहुँच और गहन प्रसार सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्य बिंदु

परिचय:

- ❶ यह एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है, जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के **युवा कार्य विभाग (DoYA)** के अंतर्गत, **डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC)**, **इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा विकसित किया गया है।
- ❷ इसका उद्देश्य युवाओं को निर्बाध मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से स्वयंसेवा, इंटरशिप, मार्गदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करना है।
- ❸ यह वर्तमान में हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है तथा धीरे-धीरे इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को भी जोड़ा जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ❶ सत्यापित अवसर: स्वयंसेवा, इंटरशिप, मेंटरशिप और अनुभवात्मक शिक्षा।
- ❷ डिजिटल मान्यता: बैज, प्रमाण-पत्र और व्यक्तिगत युवा प्रोफाइल।
- ❸ कैरियर सशक्तीकरण: कौशल निर्माण संसाधन और एआई-सक्षम रिज्यूमे निर्माण।
- ❹ युवा अभियान: प्रमुख कार्यक्रमों और नागरिक पहलों में सक्रिय भागीदारी।
- ❺ इंटरैक्टिव लर्निंग: **विकसित भारत युवा नेता संवाद (VBYLD) 2026** क्विज़ में भागीदारी।
- ❻ CSC के साथ एकीकरण: 5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के विशाल नेटवर्क का लाभ लेते हुए अब **माई भारत** पोर्टल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित होगा, जिससे युवाओं का निर्बाध पंजीकरण संभव होगा और VBYLD क्विज़ जैसी पहलों में उनकी भागीदारी संभव होगी।

❖ **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 को लॉन्च किया गया **माई भारत प्लेटफॉर्म** 1.81 करोड़ से अधिक युवाओं और 1.20 लाख संगठनों के साथ भारत के सबसे बड़े युवा-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बन गया है, जो अमृत काल के दौरान युवाओं की सहभागिता, नेतृत्व तथा राष्ट्र निर्माण के लिये एक डिजिटल आधार के रूप में कार्य कर रहा है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने **श्यामजी कृष्ण वर्मा** को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भारत के **स्वतंत्रता संग्राम** के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करते हुए युवाओं से उनकी निडर साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का अनुकरण करने का आग्रह किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- वे एक भारतीय क्रांतिकारी, देशभक्त, वकील और पत्रकार थे, जिनका जन्म 4 अक्तूबर, 1857 को मांडवी, गुजरात में हुआ था।
- लंदन में उन्होंने वर्ष 1905 में **इंडियन होम रूल सोसाइटी** की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना था।
- उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के लिये छात्रावास और बैठक-स्थल के रूप में 'इंडिया हाउस' की स्थापना की।
- उन्होंने '**द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट**' नामक पत्रिका भी शुरू की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना था।
- वे **बॉम्बे आर्य समाज** के पहले अध्यक्ष थे और **वीर सावरकर** से प्रभावित थे।
- ब्रिटिश आलोचना के प्रत्युत्तर में वे इंग्लैंड से पेरिस चले गए और तत्पश्चात् **प्रथम विश्वयुद्ध** के दौरान जिनेवा में स्थायी रूप से बस गए, जहाँ 30 मार्च, 1930 को उनका निधन हो गया।
- उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियाँ स्वतंत्र भारत में लाई जाएँ, यह इच्छा अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन **मुख्यमंत्री** नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी की गई।
- उनकी स्मृति में 'क्रांति तीर्थ' नामक स्मारक का निर्माण मांडवी के निकट किया गया, जिसका उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विश्व कपास दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पबित्रा मार्गेरिता ने 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में **विश्व कपास दिवस 2025** समारोह में भाग लिया।

- यह कार्यक्रम **वस्त्र मंत्रालय** तथा **भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI)** द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका विषय था- 'कपास 2040: प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धात्मकता'।

मुख्य बिंदु

परिचय:

- विश्व कपास दिवस की **स्थापना वर्ष 2019** में की गई थी, जब **उप-सहारा अफ्रीका** के चार कपास उत्पादक देशों (**बेनीन, बुर्किना फासो, चाड और माली**), जिन्हें सामूहिक रूप से "**कॉटन फोर**" (Cotton Four) कहा जाता है, ने 7 अक्टूबर को **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** को यह दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था।

उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य **अल्प विकसित देशों** के कपास और कपास से संबंधित उत्पादों के लिये **वैश्विक बाज़ार तक पहुँच** प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति **जागरूकता उत्पन्न करना** है।
- साथ ही यह **सतत व्यापार नीतियों** को बढ़ावा देने और **विकासशील देशों** को कपास मूल्य शृंखला के प्रत्येक चरण से अधिक **लाभ प्राप्त करने** में सक्षम बनाना है।

कपास से संबंधित तथ्य:

- शीर्ष पाँच कपास उत्पादक देश **चीन, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान** हैं, जिनकी कुल मिलाकर वैश्विक उत्पादन में **तीन-चौथाई** से अधिक हिस्सेदारी है।
 - भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल वैश्विक कपास उत्पादन का **23%** है।
- कपास से विश्व में लगभग **2.4 करोड़ उत्पादकों** को **आजीविका मिलती है** तथा **10 करोड़** से अधिक परिवारों को लाभ मिलता है।
- कपास विश्व में **पॉलिएस्टर** के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रेशा है, जो कुल रेशा मांग का लगभग **20%** है।
- लगभग **80% कपास का उपयोग परिधानों में किया जाता है**, शेष कपास का उपयोग घरेलू वस्त्रों और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।

भारत में नियंत्रण प्रणाली:

- भारतीय कपास निगम** की स्थापना **जुलाई 1970** में **वस्त्र मंत्रालय** के अधीन की गई थी।
- इसका उद्देश्य **मूल्य समर्थन उपायों के माध्यम से कपास के मूल्य स्थिरीकरण** को सुनिश्चित करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह निगम **घरेलू वस्त्र उद्योग का व्यावसायिक खरीद परिचालन के माध्यम से समर्थन** करता है, विशेष रूप से कम उत्पादन वाले मौसम के दौरान।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विश्व पर्यावास दिवस

चर्चा में क्यों ?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में “संकट के लिये शहरी समाधान” विषय के साथ विश्व पर्यावास दिवस 2025 मनाया।

♦ इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और तीव्र शहरीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु शहरों को अधिक लचीला, समावेशी तथा सतत् बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य बिंदु

♦ पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में घोषित किया।
- यह दिवस पहली बार वर्ष 1986 में “आश्रय मेरा अधिकार है” थीम के साथ मनाया गया था और नैरोबी इसका मेज़बान शहर था।

♦ उद्देश्य:

- यह दिवस आवास की स्थिति पर विचार करने तथा सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त आश्रय तक पहुँच के मौलिक अधिकार पर जोर देने के लिये मनाया जाता है।

♦ विषय 2025:

- 6 अक्टूबर को मनाए गए विश्व पर्यावास दिवस 2025 का विषय “शहरी संकट प्रतिक्रिया” था।
- यह जलवायु परिवर्तन और संघर्षों जैसी चुनौतियों से उत्पन्न शहरी असमानता को संबोधित करने तथा प्रभावी संकट प्रतिक्रिया उपकरणों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

स्कॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार

- ♦ संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम (UN-Habitat) द्वारा वर्ष 1989 में शुरू किया गया स्कॉल ऑफ ऑनर अवार्ड मानव बस्तियों के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- ♦ यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देता है:
 - आश्रय प्रावधान: पर्याप्त और सुलभ आवास।
 - निराश्रित लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालना।
 - संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में नेतृत्व।
 - शहरी जीवन की गुणवत्ता और मानव बस्तियों में सुधार करना।

93वाँ वायुसेना दिवस

चर्चा में क्यों ?

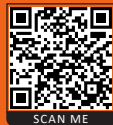
एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 93वें वायुसेना दिवस पर राष्ट्र को शुभकामनाएँ दीं और उन साहसी वायु सैनिकों को सम्मानित किया, जिन्होंने त्याग, समर्पण और कौशल के साथ देश की रक्षा की।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

परिचय:

- यह दिवस 8 अक्तूबर, 1932 को भारतीय वायुसेना (IAF) की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 अक्तूबर को मनाया जाता है।
- भारतीय वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान 1 अप्रैल, 1933 को हुई, जिसने दशकों से भारत की रक्षा को आकार देने वाली वायु शक्ति की नींव रखी।
- सीमित कार्मिक और विमानों वाली छोटी सेना से भारतीय वायुसेना अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गई है, जो विभिन्न सैन्य और मानवीय मिशनों में सक्रिय है।

आदर्श वाक्य:

- भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य 'नभः स्पर्श दीप्तम्' है, जो भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है।

विषय:

- इस वर्ष का विषय "ऑपरेशन सिंदूर में बल का योगदान" है।

समारोह:

- इस वर्ष के समारोह में **राफेल, Su-30MKI, C-17 ग्लोबमास्टर, अपाचे गार्जियन** और अन्य विमानों के साथ भव्य फ्लाईपास्ट, साथ ही परेड, एयर शो तथा भारतीय वायुसेना की तकनीकी प्रगति एवं परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियाँ शामिल थीं, साथ ही प्रतिष्ठित **मिग-21** को विदाई दी गई।
- यह परेड उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर बेस पर आयोजित की गई।
- हेरिटेज फ्लाइट के भाग के रूप में पुनर्स्थापित हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) विमान**, जो कि पहला स्वदेशी निर्मित भारतीय वायुसेना का विमान है, को भी पहली बार प्रदर्शित किया गया।
- पारंपरिक फ्लाईपास्ट और हवाई प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष के वायुसेना दिवस समारोह का समापन होगा।

70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों ?

70वें हुंडई फिल्मफेयर पुरस्कार 2025, जो 11 अक्तूबर, 2025 को EKA एरेना, अहमदाबाद में गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित किये गए, हिंदी सिनेमा में उत्कृष्टता का एक विशिष्ट उत्सव था।

BEST ACTOR In a leading role (Male) ABHISHEK BACHCHAN I WANT TO TALK 		BEST ACTOR (CRITICS') RAJKUMMAR RAO SRIKANTH 	
BEST ACTOR In a leading role (Female) ALIA BHATT JIGRA 		BEST ACTRESS (CRITICS') PRATIBHA RANTA LAAPATAA LADIES 	
		BEST DIRECTOR KIRAN RAO LAAPATAA LADIES 	

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- परिचय: यह समारोह शाहरुख खान और करण जौहर द्वारा होस्ट किया गया, जो 18 वर्षों के बाद फिल्मफेयर मंच पर फिर से मिले। यह आयोजन चमक-दमक और यादों का संगम था, जो सिनेमा की सात दशकों की उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिये आयोजित किया गया।
- उद्देश्य: वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का उत्सव मनाना और कई श्रेणियों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना।
- मुख्य जीत: 'लापता लेडीज़' ने रात की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 13 ट्रॉफियाँ जीतीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म (Best Film) शामिल है और इस तरह 'गली बॉय' (2019) का रिकॉर्ड बनाए रखा, जिसमें रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट थे।
 - अभिनय श्रेणियों में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) पुरस्कार साझा किया, जबकि आलिया भट्ट ने अपने शानदार रोल के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफी जीती।

टॉप इंडिविजुअल विनर्स

नाम	पुरस्कार/अवार्ड्स	फिल्म/फिल्में
किरण राव	सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	लापता लेडीज़
शूजित सरकार	क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म	आई वांट टू टॉक
स्नेहा देसाई	बेस्ट स्क्रीनप्ले एंड बेस्ट डायलॉग	लापता लेडीज़
राम संपथ	बेस्ट म्यूज़िक एल्बम एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर	लापता लेडीज़
अचिंत ठक्कर	RD बर्मन अवार्ड (संगीत में उभरती प्रतिभा)	जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज़ माही
ज़ीनत अमान, श्याम बेनेगल (पोस्टह्यूमसली)	लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिये सम्मानित

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों ?

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) 2025 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम (Tele-MANAS) के तहत कई नई सुविधाओं की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु

- ऐप सुधार: Tele-MANAS मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को कहीं भी और कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया जाता है।
 - ऐप में अब बहुभाषी इंटरफेस, चैटबोट, पहुँच सुधार और आपातकालीन प्रतिक्रिया मॉड्यूल जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
 - ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओड़िया और पंजाबी) में उपलब्ध है, इसके अलावा अंग्रेज़ी तथा हिंदी में भी उपलब्ध है।
 - सुलभता सुविधाएँ इसे दिव्यांग व्यक्तियों, विशेषकर दृष्टिहीन लोगों के लिये उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाती हैं।
 - चैटबोट "अस्मी" (Asmi) उपयोगकर्ताओं को संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुँचने की सुविधा देता है।
 - आपातकालीन मॉड्यूल संकट के समय त्वरित मार्गदर्शन और सहायता सुनिश्चित करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ **मेंटल हेल्थ एंबेसडर:** मंत्री ने घोषणा की कि दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- ❖ **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस:**
 - **परिचय:** विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, संवाद को प्रोत्साहित करना और सभी के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने के प्रयासों को सक्रिय करना है।
 - **थीम:** 2025 की थीम, “सेवाओं तक पहुँच- आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य” (Access to Services - Mental Health in Catastrophes and Emergencies), यह दर्शाती है कि **प्राकृतिक आपदाओं**, सशस्त्र संघर्षों और महामारी जैसी संकट की स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है।

विश्व मानक दिवस

चर्चा में क्यों ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने 14 अक्टूबर, 2025 को **विश्व मानक दिवस (World Standards Day)** कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

- ❖ यह कार्यक्रम **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा आयोजित किया गया था, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (NITS) में आयोजित इस समारोह में भारत का **राष्ट्रीय लाइटिंग कोड 2025 (National Lighting Code of India 2025)** जारी किया गया, इसके साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) तथा **ऑनलाइन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट (OSD) मॉड्यूल** को भी **BIS मानक पोर्टल** पर लॉन्च किया गया।
- ❖ **विश्व मानक दिवस:**
 - **परिचय:** विश्व मानक दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों (Standards) के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था।
 - यह दिवस **अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)** ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) और **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** के सहयोग से स्थापित किया था, ताकि वैश्विक स्तर पर मानक विकसित करने वाले समुदाय तथा उनके योगदान का सम्मान किया जा सके।
 - **उद्देश्य:** विश्व मानक दिवस उन मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाता है, जो **गुणवत्ता, सुरक्षा और सततता** सुनिश्चित करते हैं। यह उन विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो इन ढाँचों को बनाने के लिये कार्य करते हैं।
 - **थीम:** वर्ष 2025 की थीम, “A Shared Vision for a Better World: Standards for Sustainable Development Goals” अर्थात् एक बेहतर विश्व के लिये साझा दृष्टि: सतत् विकास लक्ष्यों हेतु मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उस भूमिका पर जोर देती है, जो संयुक्त राष्ट्र **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** को प्राप्त करने के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- ❖ BIS भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक संस्थान है, जिसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास के लिये **BIS अधिनियम, 2016** के तहत स्थापित किया गया।
- 🌀 इसकी स्थापना प्रारंभ में **भारतीय मानक संस्था (ISI)** के रूप में हुई थी, जो **6 जनवरी, 1947** को अस्तित्व में आई।
- ❖ इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
- ❖ BIS विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जैसे कि **उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क)**, सोने और चांदी के आभूषणों की **हॉलमार्किंग**, **ईको मार्क योजना** (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिये)।

भारत-दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास (IN-RoKN)

चर्चा में क्यों ?

भारत-दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास (IN-RoKN) का पहला संस्करण 13 अक्टूबर, 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल बेस में शुरू हुआ, जो **भारतीय नौसेना (IN)** और कोरिया गणराज्य नौसेना (RoKN) के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर है।



मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** पहला IN-RoKN अभ्यास दो अलग-अलग चरणों- **हार्बर फेज़ और सी फेज़** में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों समुद्री सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी), आपसी समझ तथा विश्वास को बढ़ाना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- **हार्बर फेज़:** इस चरण में, दोनों देशों के नौसैनिक अधिकारी क्रॉस-डेक विज़िट, पेशेवर अनुभवों का आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, खेलकूद गतिविधियों और क्रॉस-ट्रेनिंग सत्रों में शामिल होंगे। INS सह्याद्रि के कमांडिंग ऑफिसर भी वरिष्ठ RoKN अधिकारियों तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से शिष्टाचार करेंगे।
- **सी फेज़:** समुद्री चरण में INS सह्याद्रि और ROKS Gyeongnam के बीच जटिल संयुक्त अभ्यास एवं संचालन संबंधी अभ्यास होंगे, जिनका उद्देश्य सामरिक समन्वय तथा परिचालन सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- ◆ **INS सह्याद्रि:** INS सह्याद्रि एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित शिवालिक-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे वर्ष 2012 में कमीशन किया गया तथा यह ईस्टर्न नेवल कमांड के ईस्टर्न फ्लीट के अधीन सेवाएँ प्रदान करता है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है।
- यह भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' (Self-Reliant India) पहल और उसकी स्वदेशी शिपबिल्डिंग क्षमताओं का प्रतीक है।
- ◆ **रणनीतिक महत्त्व:** जैसे-जैसे **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र** का भू-राजनीतिक महत्त्व बढ़ रहा है, भारत और कोरिया गणराज्य ने साझा हितों, आपसी सम्मान तथा सामान्य मूल्यों पर आधारित सुदृढ़ समुद्री साझेदारी विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की दोबारा पुष्टि की है।

विश्व खाद्य दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्तूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और संधारणीय कृषि के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

- ◆ **परिचय:** विश्व खाद्य दिवस **संयुक्त राष्ट्र (UN)** द्वारा 16 अक्तूबर, 1945 को स्थापित **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है।
- विश्व खाद्य दिवस 1979 में FAO की 20वीं महासभा के दौरान अस्तित्व में आया और 1984 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृति प्रदान की।
- **भोजन का अधिकार** 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- ◆ **थीम:** वर्ष 2025 के लिये थीम है "बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य साथ-साथ", जो एग्रीफूड सिस्टम को बदलने में वैश्विक सहयोग की शक्ति को उजागर करती है।
- ◆ **भारत की स्थिति:** पिछले दशक में भारत का अन्न उत्पादन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है, जो दृढ़ कृषि विकास को दर्शाता है।
 - फल और सब्जियों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है तथा इसी अवधि में यह 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया।
 - भारत अब दूध और बाजरे (मिलेट्स) के उत्पादन में विश्व में **प्रथम स्थान** पर है, जबकि मछली, फल तथा सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। वर्ष 2014 के बाद से शहद एवं अंडे का उत्पादन दोगुना हो गया है।
- ◆ **भारत की पहलें:** **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013**, **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**, **पीएम पोषण (POSHAN) योजना**, **अंत्योदय अन्न योजना**, **राइस फोर्टिफिकेशन** और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) जैसी प्रमुख पहलें भारत की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



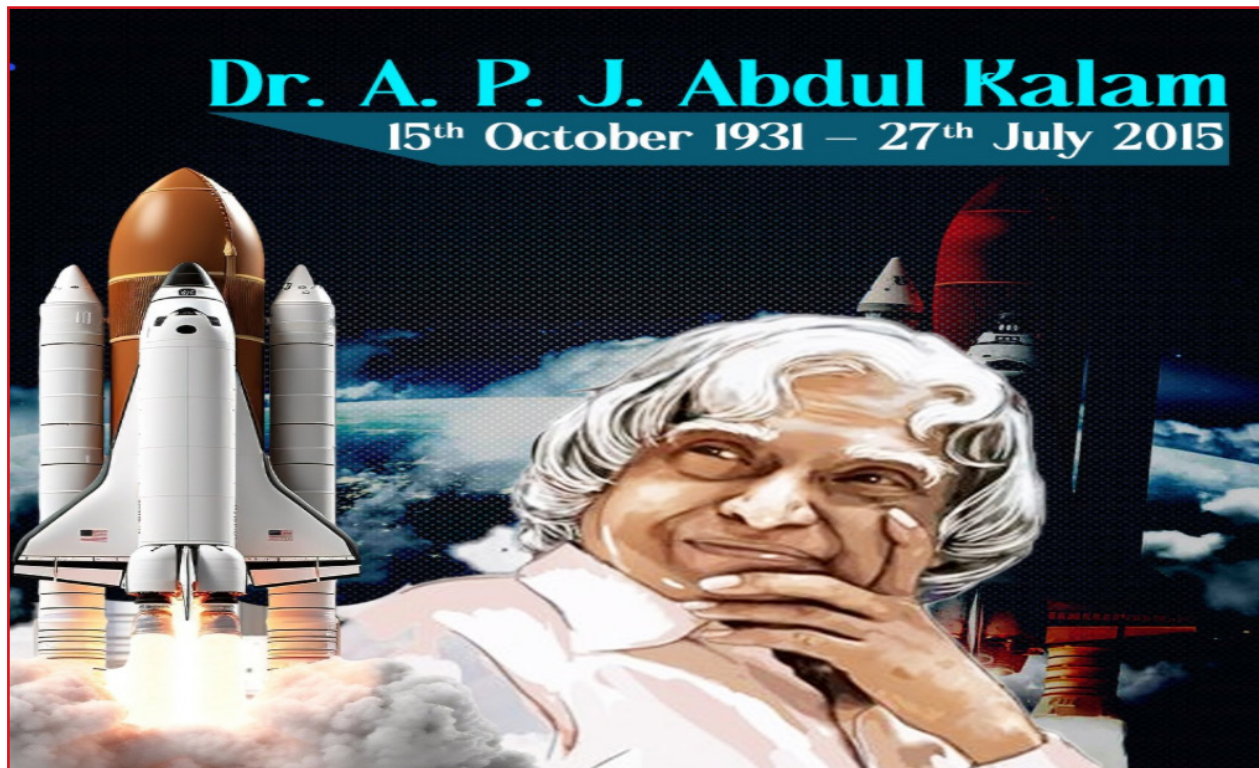
दृष्टि लर्निंग
ऐप



डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती

चर्चा में क्यों ?

15 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।



मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** डॉ. अवुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त की थी।
- ❖ **अंतरिक्ष अनुसंधान:** वे भारत के पहले स्वदेशी **उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III)** के परियोजना निदेशक रहे, जिसने जुलाई, 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे भारत विशिष्ट “स्पेस क्लब” का सदस्य बना।
 - ⦿ उन्होंने इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से **PSLV कॉन्फिगरेशन** के निर्माण में, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं की आधारशिला बन गया।
- ❖ **रक्षा विकास:** एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, उन्होंने **AGNI** और **PRITHVI** जैसी प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के विकास तथा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- जुलाई, 1992 से दिसंबर, 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और **रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DRDO)** के सचिव के रूप में, डॉ. कलाम ने भारत के मिसाइल प्रणालियों के सशस्त्रीकरण का नेतृत्व किया तथा सफल **पोखरण-II परमाणु परीक्षणों** की देख-रेख की, जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना।
- उनका योगदान रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता तक विस्तृत था, जिसमें **लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA)** के विकास में उनकी अहम भूमिका शामिल है।
- ♦ **विकसित भारत का दृष्टिकोण:** उनका नेतृत्व टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (TIFAC) तक विस्तृत था, जहाँ उन्होंने अध्यक्ष के रूप में **टेक्नोलॉजी विज़न 2020** परियोजना का नेतृत्व किया।
- ♦ **पुस्तकें:** उनकी रचनाएँ जैसे- **“विंग्स ऑफ फायर”, “इंडिया 2020 - ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम”, “माय जर्नी”** और **“इग्नाइटेड माइंड्स - अनलीशिंग द पावर विदिन इंडिया”** - अनेक भाषाओं में अनुदित की गई हैं, जो आज भी विश्वभर में लोकप्रिय हैं।
- ♦ **सम्मान और पुरस्कार:** उन्हें 30 मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त हुईं तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों जैसे- **पद्म भूषण (1981)**, **पद्म विभूषण (1990)** और **भारत रत्न (1997)** से सम्मानित किया गया।
- **भारत के राष्ट्रपति:** 25 जुलाई, 2002 को डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जहाँ उन्होंने विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उनकी राष्ट्रपति अवधि का प्रमुख लक्ष्य था- भारत को वर्ष 2020 तक एक वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित करना। उन्होंने वैज्ञानिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय गौरव और युवा सशक्तीकरण की एक अमिट विरासत स्थापित की।

विशाखापत्तनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब

चर्चा में क्यों ?

गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अत्याधुनिक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** हब स्थापित करने के लिये वर्ष 2026 से 2030 तक अगले पाँच वर्षों में **15 अरब डॉलर** निवेश करने की योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- ♦ **परिचय:** इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित **‘भारत AI शक्ति’** कार्यक्रम के दौरान की गई, जहाँ गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना पर **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी** से चर्चा की थी।
- ♦ **सबसे बड़ा AI हब:** विशाखापत्तनम में बनने वाला नया डेटा सेंटर अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब होगा।
 - यह पहल गूगल की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी इस वर्ष लगभग **85 अरब डॉलर** का निवेश करके अपने डेटा सेंटर नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि विश्वभर में बढ़ती AI सेवाओं की मांग को पूरा किया जा सके।
- ♦ **सेवाएँ:** गूगल AI हब पूरी तरह से AI समाधान प्रदान करेगा, जिसमें गूगल के स्वामित्व वाले **टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU)** का उपयोग किया जाएगा, जो पारंपरिक चिप्स की तुलना में दोगुनी ऊर्जा-कुशल हैं।
 - यह हब डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहित करेगा ताकि भारत की **सॉवरेन AI आवश्यकताओं** का पालन हो सके, साथ ही गूगल के उन्नत AI मॉडल जैसे- **जेमिनी (Gemini)**, **इमेजिन (Imagine)** और **वीओ (Vevo)** को भी तैनात किया जाएगा।
- ♦ **सहयोग:** इस महत्वाकांक्षी पहल का समर्थन करने के लिये **अडानी समूह** और **एयरटेल** ने गूगल के साथ साझेदारी की है। इसके अंतर्गत आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक **न्यू इंटरनेशनल सबसिया गेटवे** भी शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



समुद्र शक्ति का पाँचवाँ संस्करण

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना 14 से 17 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'समुद्र शक्ति' के पाँचवें संस्करण की मेजबानी कर रही है।



मुख्य बिंदु

- ♦ **परिचय:** इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य समुद्र और तट दोनों पर पेशेवर तथा परिचालनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से दोनों देशों के बीच अंतरसंचालन क्षमता (interoperability) को बढ़ाना तथा समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- ♦ **भाग लेने वाली इकाइयाँ:**
 - **INS कवरत्ती:** भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की एक पनडुब्बी-रोधी युद्धक (Anti-Submarine Warfare) कॉर्वेट।
 - **KRI जॉन ली:** इंडोनेशियाई नौसेना की एक कॉर्वेट, जो एक एकीकृत हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ♦ **हार्बर फेज:** हार्बर चरण में गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे- क्रॉस-डेक दौरे, संयुक्त योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन और सबजेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज (SMEE) कार्यक्रम के तहत पेशेवर आदान-प्रदान, जो दोनों देशों के नौसैनिक कर्मियों के बीच पेशेवर संवाद तथा सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं।
- ♦ **सी चरण:** सी चरण में जटिल और उच्च-गतिशीलता वाले समुद्री अभियान होंगे, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच टैक्टिकल समन्वय (tactical coordination) में सुधार करना है। इन अभियानों में हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास, हवाई रक्षा अभ्यास (Air Defence Exercises), हथियार फायरिंग ड्रिल्स और विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सिज़र (VBSS) ऑपरेशन्स शामिल होंगे।
- ♦ **महत्त्व:** यह अभ्यास इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- ♦ भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य सैन्य अभ्यास: गरुड शक्ति, IND-INDO CORPAT

संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025, जिसे भारतीय सेना ने 14 से 16 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया, में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं को एकत्रित किया गया, जो वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मुख्य बिंदु

- ❖ **परिचय:** इस सम्मेलन में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जिनमें अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, मिक्स, इथियोपिया, फ्रांस, घाना, भारत, इटली, केन्या, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम शामिल हैं।
- ❖ इस कार्यक्रम में रक्षा प्रदर्शनियाँ भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों के लिये साझा क्षमताओं का निर्माण करना है।
- ❖ **उद्देश्य:** UNTCC एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य परिचालनिक चुनौतियों, विकसित हो रहे खतरों, अंतर-संचालन क्षमता, निर्णय-निर्माण में समावेशिता और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण की भूमिका पर चर्चा करना है।
- ❖ **भारत,** जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, ने **भविष्य के शांति स्थापना अभियानों के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा, ज्ञान साझा करने और आपसी समझ विकसित करने** के उद्देश्य से इस उच्च स्तरीय मंच का आयोजन किया है।
- ❖ **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन:** प्रमुखों ने भारतीय सेना द्वारा एकीकृत, **आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी** का प्रदर्शन देखा, जिसमें विभिन्न स्वदेशी सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया।
- ❖ **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिये 4C सूत्र:** रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति स्थापना में उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु **परामर्श (Consultation), सहयोग (Cooperation), समन्वय (Coordination) और क्षमता निर्माण (Capacity Building)** के मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसे 4C सूत्र कहा गया।
- ❖ उन्होंने यह भी बताया कि **नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर UN पीसकीपिंग** ने 90 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे शांति सैनिकों के बीच **अंतरसंचालन क्षमता (Interoperability)** के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNPK)

- ❖ पहला UNPK मिशन, **संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO)**, मई 1948 में स्थापित किया गया था ताकि इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच **आर्मिस्टिस समझौते** की निगरानी एक छोटे सैन्य पर्यवेक्षक दल के माध्यम से की जा सके।
- ❖ उन्हें **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** द्वारा युद्धविराम और शांति समझौतों का समर्थन करने के लिये तैनात किया जाता है तथा इन्हें **ब्लू हेलमेट्स** कहा जाता है क्योंकि हल्का नीला रंग **UN ध्वज पर शांति का प्रतीक** है।
- ❖ वर्तमान में, 119 देशों के 61,000 से अधिक सैन्य और पुलिस शांति सैनिक तथा 7,000 से अधिक नागरिक कर्मी 11 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

डॉ. पिंकी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत की पूर्व **एडिशनल सॉलिसिटर जनरल**, को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि वर्ष 2024 में पूर्व **सर्वोच्च न्यायालय** के न्यायाधीश संजय किशन कौल की उसी न्यायालय में नियुक्ति के बाद हुआ है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





डॉ. पिकी आनंद

- ♦ **पृष्ठभूमि:** हार्वर्ड लॉ स्कूल की स्नातक और इन्लैक्स स्कॉलर, डॉ. पिकी आनंद के पास 40 वर्षों से अधिक का विधिक अनुभव है। उन्होंने भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (2014-2020) के रूप में कार्य किया और उन्हें संवैधानिक कानून, सिविल मध्यस्थता तथा आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है।
- ♦ **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व:** उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया है, जिनमें ब्रिक्स (BRICS) शामिल हैं; ब्रिक्स लीगल फोरम की संस्थापक सदस्य भी हैं।
- ♦ **सम्मान:** उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया।

बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC)

- ♦ **बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Bahrain International Commercial Court- BICC)** की स्थापना जटिल सीमा पार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिये की गई है। यह न्यायालय 5 नवंबर, 2025 को न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना कार्य आरंभ करेगा, जिसमें बहरीन के राजपरिवार और प्रधानमंत्री की उपस्थिति होगी।
- ♦ BICC की अध्यक्षता प्रसिद्ध मध्यस्थता विशेषज्ञ **जान पॉल्सन** कर रहे हैं और इसमें 17 न्यायाधीश शामिल हैं- जिनमें 7 महिलाएँ एवं 10 पुरुष हैं, जो विश्व के विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ♦ यह न्यायालय मार्च, 2024 में बहरीन और सिंगापुर के बीच हुई एक संधि के तहत स्थापित किया गया है तथा इसका ढाँचा सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Singapore International Commercial Court- SICC) के मॉडल पर आधारित है ताकि वाणिज्यिक विवाद समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि

चर्चा में क्यों ?

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के सम्मान में प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है।

- पिपिंग समारोह नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी की उपस्थिति में औपचारिक रूप से यह रैंक प्रतीक/चिह्न (Rank Insignia) प्रदान किया।



मुख्य बिंदु

- परिचय:** 24 दिसंबर, 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गाँव में जन्मे नीरज चोपड़ा एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और भारत के सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं।
- भारतीय सेना में यात्रा:**
 - नीरज चोपड़ा अगस्त, 2016 में भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में नायब सूबेदार (Naib Subedar) के रूप में शामिल हुए थे तथा वर्ष 2021 में उन्हें एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिये सूबेदार (Subedar) के पद पर पदोन्नत किया गया।
 - वर्ष 2022 में, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें सूबेदार मेजर (Subedar Major) पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय सेना के सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान 'परम विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया गया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- अप्रैल, 2025 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रसेवा और उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों की मान्यता में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल (Honorary Lieutenant Colonel) की उपाधि प्रदान की।

❖ खेल में प्राप्त उपलब्धियाँ:

- टोक्यो ओलंपिक 2020: ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा।
- विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023: स्वर्ण पदक जीता, जिससे वैश्विक एथलेटिक्स में भारत की उपस्थिति और दृढ़ हुई।
- पेरिस ओलंपिक 2024: रजत पदक प्राप्त किया, जिससे उनका निरंतर उच्च प्रदर्शन स्तर बना रहा।
- एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल: कई स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक स्पर्धा में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की।
- डायमंड लीग एवं अन्य प्रतियोगिताएँ: लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया तथा वर्ष 2025 में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो (Personal Best Throw) कर भारतीय एथलेटिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया।

❖ पुरस्कार एवं सम्मान:

- विशिष्ट सेवा पदक (2023)
- परम विशिष्ट सेवा पदक (2022)
- पद्मश्री (2022)
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2021)
- अर्जुन पुरस्कार (2018)

अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस और ' #23for23 ' पहल

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 23 अक्तूबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस मनाया, जिसमें ' #23for23 ' शीर्षक के तहत एक विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। इस अभियान ने लोगों को 23 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिये समर्पित करने हेतु प्रेरित किया, ताकि स्नो लेपर्ड (हिम तेंदुए) और उनके संवेदनशील उच्च ऊँचाई वाले आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

मुख्य बिंदु

- ❖ परिचय: ' #23for23 ' अभियान को वर्ष 2023 के लिये 23 मिनट की सक्रिय भागीदारी का प्रतीक बनाकर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में जागरूकता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
- यह अभियान ग्लोबल स्नो लेपर्ड और ईकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) के अंतर्गत, तथा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट वर्ल्डवाइड के सहयोग से आयोजित किया गया।
- ❖ भारत की संरक्षण उपलब्धियाँ:
 - भारतीय हिमालय में की गई पहली स्नो लेपर्ड गणना में 718 स्नो लेपर्ड पाए गए, जिनमें से 477 लद्दाख में हैं।
 - भारत ने उच्च ऊँचाई पर स्थित हिमालयों के लिये स्नो लेपर्ड को एक प्लैगशिप (मुख्य) प्रजाति के रूप में चिह्नित किया है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस: यह दिवस वर्ष 2013 में स्थापित हुआ, जब किर्गिजस्तान में बिशकेक घोषणा को अपनाने के बाद उन 12 देशों ने, जिनमें स्नो लेपर्ड की आबादी है, संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ स्नो लेपर्ड की मेज़बानी करने वाले देश: अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान।

स्नो लेपर्ड (Panthera uncia): तथ्य

- ❖ परिचय: मध्यम आकार की बिल्लियाँ जो अपनी चतुराई के लिये जानी जाती हैं और कठोर, **ऊँचाई वाले वातावरण में जीवित** रहने की क्षमता रखती हैं।
- ❖ पर्यावास: **मध्य और दक्षिण एशिया** के पहाड़ों में मूल निवासी, आमतौर पर 9,800 से 17,000 फीट की ऊँचाई पर पाई जाते हैं।
- ❖ वन्य में लगभग 3,500 से 7,000 स्नो लेपर्ड होने का अनुमान लगाया गया है।
- ❖ विशेषताएँ: मोटे, धूसर-सफेद फर से युक्त, जो बर्फ और चट्टानों के बीच छिपने में सहायता करता है।
- ❖ पारिस्थितिक महत्त्व: ये शीर्ष शिकारी तथा **संकेतक प्रजाति** के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति उच्च ऊँचाई पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है।
- ❖ इनके शिकार से **गिद्ध** और **भेड़िये** जैसे अपशिष्ट का सेवन करने वाले जीवों को भोजन मिलता है, जिससे अन्य प्रजातियों का समर्थन होता है।

हिम तेंदुआ (Snow Leopard)



प्रायः इसे "Ghost of the Mountains" अर्थात "पहाड़ों का भूत" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

● आवास

मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र
हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों की संख्या (12) - भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान

● भारत में

पश्चिमी हिमालय : जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश
पूर्वी हिमालय : उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश

● प्रमुख स्थान

हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख
(इसे हिम तेंदुओं की 'वैश्विक राजधानी' के रूप में भी जाना जाता है)
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड
कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम

● खतरे

- मानव- हिम तेंदुआ संघर्ष
- शिकार एवं आवास की क्षति
- अवैध शिकार
- जलवायु परिवर्तन

● संरक्षण स्थिति

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
CITES - परिशिष्ट - I
भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची 1

● संरक्षण हेतु प्रयास

- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम
- हिमाल संरक्षक - सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL)
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम - पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025

चर्चा में क्यों ?

भारत ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में नौवें स्थान पर पहुँचकर पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा बाली, इंडोनेशिया में जारी की गई है।

❖ यह पूर्व में हुए मूल्यांकन में दसवें स्थान से सुधार को दर्शाता है और देश के सतत वन प्रबंधन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

मुख्य बिंदु

❖ **परिचय:** वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA), जिसे FAO द्वारा संचालित किया जाता है, विश्व के वन संसाधनों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी स्थिति, प्रबंधन और उपयोग शामिल हैं। यह देशों द्वारा प्रस्तुत डेटा पर आधारित होता है, जिसे विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

● यह रिपोर्ट सतत विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा, पेरिस जलवायु समझौता, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा और संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2017-2030 के लिये वन रणनीतिक योजना जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की निगरानी में सहायता करती है।

❖ **भारत के संबंध में निष्कर्ष:**

- रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर है, जिससे देश विश्व में नौवें स्थान पर है।
- वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत अभी भी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जो उसके बड़े पैमाने पर वनीकरण और संरक्षण पहलों की सफलता को दर्शाता है।
- FAO रिपोर्ट में भारत के कृषि-वानिकी (एग्रोफॉरेस्ट्री) क्षेत्र को भी उजागर किया गया है। 91 देशों में 55.4 मिलियन हेक्टेयर एग्रोफॉरेस्ट्री भूमि में भारत और इंडोनेशिया मिलकर लगभग 70% वैश्विक कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रोफॉरेस्ट्री में है, जो कार्बन संग्रहण, आजीविका सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

❖ **वैश्विक रुझान:**

- FRA 2025 के अनुसार, वर्तमान में विश्व के वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई है।
- रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वनोन्मूलन (वनों की कटाई) की दर में कमी देखी गई है, हालाँकि वर्तमान दर प्रतिवर्ष 10.9 मिलियन हेक्टेयर अभी भी अधिक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- अब विश्व के आधे से अधिक जंगल दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के तहत हैं और लगभग 20% वन कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं।
- वैश्विक स्तर पर रूस सबसे ऊपर है, जिसका वन क्षेत्र 832.6 मिलियन हेक्टेयर है, इसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन का स्थान है।

पूर्वी तिमोर आसियान का 11वाँ सदस्य बना

चर्चा में क्यों ?

पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आधिकारिक रूप से **दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN)** का 11वाँ सदस्य बन गया है।

- औपचारिक रूप से इसका समावेश कुआलालंपुर में एक समारोह में हुआ, जो 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार है।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:**
 - पूर्वी तिमोर ने वर्ष 2011 में आसियान की सदस्यता के लिये आवेदन किया था, उसे वर्ष 2022 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया तथा 14 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में उसे पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई।
 - इससे पहले आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश 1999 में कंबोडिया था।
- प्रभाव:**
 - सदस्यता से पूर्वी तिमोर को आसियान के **मुक्त व्यापार समझौतों** में भाग लेने, निवेश के अवसर प्राप्त करने और व्यापक क्षेत्रीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
- पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते)**
 - पूर्वी तिमोर जिसे तिमोर-लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण-पूर्व में **तिमोर सागर**, उत्तर में वेटार जलडमरूमध्य, उत्तर-पश्चिम में ओम्बाई जलडमरूमध्य और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी तिमोर (इंडोनेशियाई प्रांत पूर्वी नुसा तेगारा का हिस्सा) से घिरा है।
 - पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है।
 - पूर्वी तिमोर, जिसे 18वीं शताब्दी में **पुर्तगाल ने उपनिवेश बनाया था**, पुर्तगाल के शासन के बाद वर्ष 1975 में इंडोनेशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण यहाँ स्वतंत्रता के लिये एक लंबा संघर्ष चला।
 - वर्ष 1999 में **संयुक्त राष्ट्र** की निगरानी में हुए **जनमत संग्रह** में, पूर्वी तिमोरियों ने स्वतंत्रता के लिये मतदान किया, जिसके कारण शांति सेना के हस्तक्षेप तक हिंसा जारी रही और वर्ष 2002 में **संयुक्त राष्ट्र** द्वारा देश को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





आसियान

- ❖ **स्थापना:** आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर द्वारा (1967)
- ❖ **संस्थापक सदस्य:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड
- ❖ **सचिवालय:** इंडोनेशिया, जकार्ता

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

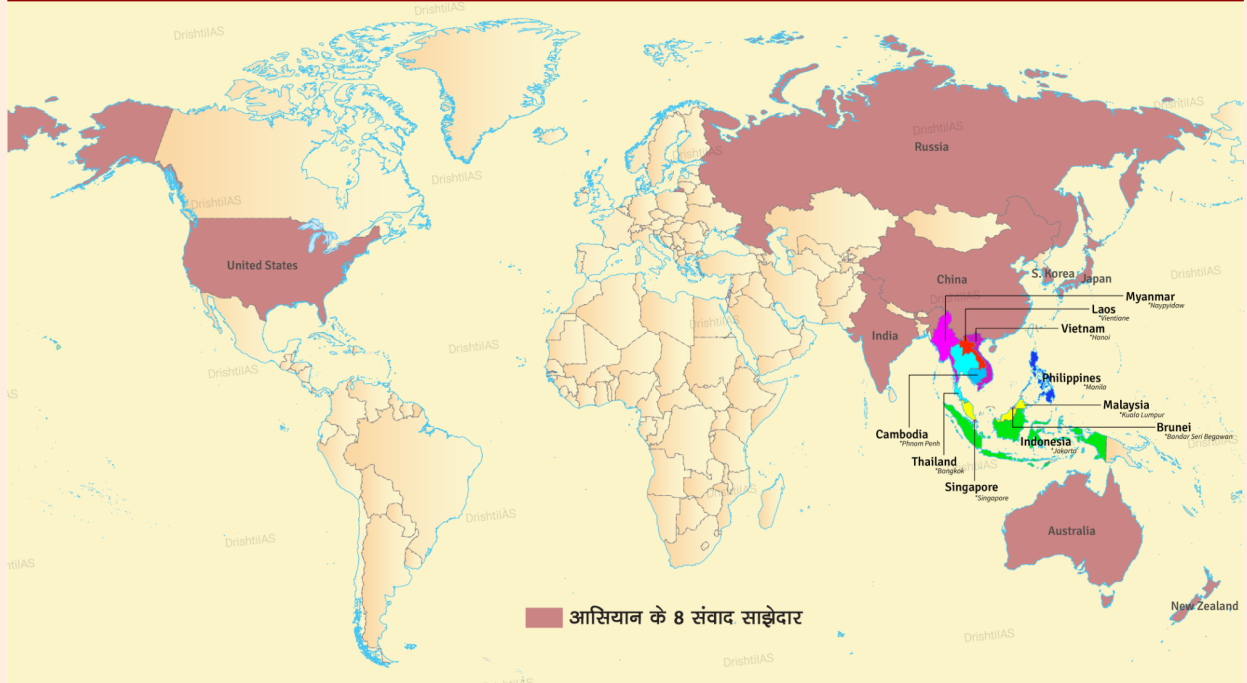


- अध्यक्षता: वार्षिक रूप से बदलती रहती है (वर्तमान में मलेशिया)
- आसियान शिखर सम्मेलन बैठक: वर्ष में दो बार आयोजित



आसियान

दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन



आसियान के 8 संवाद साझेदार

स्थापना: आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) (1967) पर हस्ताक्षर द्वारा
संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड
सचिवालय: इंडोनेशिया, जकार्ता
अध्यक्षता: वार्षिक रूप से बदलती रहती है
आसियान शिखर सम्मेलन: वर्ष में दो बार आयोजित

आसियान (ASEAN) अर्थव्यवस्था:

- संयुक्त GDP: ~3.66 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2022)
- कुल निर्यात: 1.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2021 में वैश्विक निर्यात का 8.24%)
- प्रमुख निर्यात मर्दे: मोनोलिथिक इंटिग्रेटेड सर्किट, पाम ऑयल, डेटा प्रोसेसिंग उपकरण

ADMM+बैठक: आसियान और उसके 8 संवाद साझेदारों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस और न्यूजीलैंड) के लिये मंच
 ○ पहली बार आयोजन: हनोई, वियतनाम (2010)



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर को विज्ञान रत्न

चर्चा में क्यों ?

प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरान्त **विज्ञान रत्न पुरस्कार** 2025 के लिये चयनित किया गया है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिये देश का सर्वोच्च सम्मान है।

- भारत सरकार ने **राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार** 2025 के दूसरे संस्करण की घोषणा की, जिसमें चार श्रेणियों - विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 23 व्यक्तियों तथा एक संस्थान को सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंदु

जयंत विष्णु नार्लीकर के बारे में:

- जयंत विष्णु नार्लीकर (1938–2025) एक प्रख्यात खगोल-भौतिक वैज्ञानिक थे, जो ब्रह्मांड विज्ञान, सामान्य सापेक्षता तथा ब्रह्मांड के स्थिर-अवस्था सिद्धांत पर अपने शोध कार्यों के लिये विख्यात थे।
- सर फ्रेड होयल के निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के होयल-नार्लीकर सिद्धांत का सह-विकास किया।
- वे पुणे स्थित अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल-भौतिकी केंद्र (IUCAA) के संस्थापक निदेशक रहे।
- उनके योगदान ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के मध्य सेतु का कार्य किया, जबकि उनके लोकप्रिय विज्ञान लेखन ने युवा वैज्ञानिकों की अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता:

विज्ञान श्री (विशिष्ट योगदान)	
प्राप्तकर्ता	क्षेत्र
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह	कृषि विज्ञान
यूसुफ मोहम्मद शेख	परमाणु ऊर्जा
के. थंगराज	जैविक विज्ञान
प्रदीप थलप्पिल	रसायन विज्ञान
अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित	इंजीनियरिंग विज्ञान
एस. वेंकट मोहन	पर्यावरण विज्ञान
महान एम.जे.	गणित और कंप्यूटर विज्ञान
जयन एन	अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी
विज्ञान युवा (युवा वैज्ञानिक पुरस्कार)	
जगदीश गुप्ता कपुंगती	कृषि विज्ञान
सतेन्द्र कुमार मंगरौठिया	कृषि विज्ञान
देबरका सेनगुप्ता	जैविक विज्ञान

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



दीपा अगाशे	जैविक विज्ञान
दिब्येंदु दास	रसायन विज्ञान
वलीउर रहमान	भू - विज्ञान
अर्काप्रवा बसु	इंजीनियरिंग विज्ञान
सब्यसाची मुखर्जी	गणित और कंप्यूटर विज्ञान
श्वेता प्रेम अग्रवाल	गणित और कंप्यूटर विज्ञान
सुरेश कुमार	दवा
अमित कुमार अग्रवाल	भौतिक विज्ञान
सुरहुद श्रीकांत मोरे	भौतिक विज्ञान
अंकुर गर्ग	अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मोहनशंकर शिवप्रकाशम	प्रौद्योगिकी और नवाचार
विज्ञान टीम पुरस्कार	
CSIR अरोमा मिशन	कृषि विज्ञान

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

परिचय:

- राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है।
- पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर स्थापित यह सम्मान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देता है।
- ये पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्रपति भवन में प्रदान किये जाते हैं।
- वर्ष 2023 में स्थापित इस पुरस्कार के विजेताओं की अनुशंसा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति (RVPC) द्वारा की जाती है।
- इसका पहला समारोह अगस्त, 2024 में आयोजित किया गया था।

श्रेणियाँ:

- विज्ञान रत्न: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों और योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।
- विज्ञान श्री: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये सम्मानित किया जाता है।
- विज्ञान युवा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिये 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।
- विज्ञान टीम: उत्कृष्ट सहयोगात्मक कार्य के लिये तीन या अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या नवप्रवर्तकों की टीम को प्रदान किया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



त्रिशूल अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

भारत ने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर बड़े स्तर पर तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 'त्रिशूल' प्रारंभ किया है।

- यह अभ्यास सर क्रीक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच किसी भी उकसावे या विरोध का सामना करने तथा रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने में भारत की तत्परता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

अभ्यास के बारे में:

- यह अभ्यास 30 अक्तूबर से 10 नवंबर, 2025 तक निर्धारित है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना की बड़े पैमाने पर भागीदारी शामिल है।
- इसका उद्देश्य परिचालन तत्परता, संयुक्त समन्वय और बहु-क्षेत्र युद्ध कौशल को बढ़ाना है।
- इस अभ्यास का कोड नाम "त्रिशूल" है, जबकि आंतरिक रूप से इसे "महागुर्जर" कहा जाता है।
- यह अभ्यास जैसलमेर (राजस्थान) से सर क्रीक (गुजरात) तक फैले थार रेगिस्तान को कवर करेगा।

उद्देश्य:

- मुख्य लक्ष्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त संचालन का परीक्षण तथा सुधार करना है, जिसमें भूमि, समुद्र, वायु एवं साइबर क्षेत्र शामिल हैं।
- अभ्यास में एकीकृत संचालन, डीप-स्ट्राइक मिशन, अम्फीबियस युद्ध और बहु-क्षेत्र युद्ध तैयारियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- यह अभ्यास विभिन्न कमांडों के बीच समन्वय बढ़ाने और नवीनतम स्वदेशी हथियार प्रणालियों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परखने का भी लक्ष्य रखता है।

भागीदारी:

- सेना ने 20,000 से अधिक सैनिक तैनात किये हैं, जिन्हें T-90S और अर्जुन टैंक, हॉवित्ज़र, सशस्त्र हेलीकॉप्टर तथा मिसाइल प्रणाली का समर्थन प्राप्त है।
- वायुसेना (IAF) उच्च-गति वाले "महागुर्जर" संचालन कर रही है, जिसमें राफेल और सुखोई-30MKI फाइटर जेट, परिवहन तथा ईंधन भरण विमान (IL-78), AEW&C प्रणाली एवं UAVs तैनात हैं।
- नौसेना ने सौराष्ट्र और गुजरात तटों पर फ्रिगेट तथा विध्वंसक पोत तैनात किये हैं, ताकि अम्फीबियस एवं समुद्री युद्ध अभ्यास किया जा सके।

एयरमैन को नोटिस (NOTAM):

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने अभ्यास के दौरान राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्सों में नागरिक उड़ानों को प्रतिबंधित करने के लिये एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी किया है, जबकि पाकिस्तान ने 28-29 अक्तूबर 2025 के आसपास अपने केंद्रीय तथा दक्षिणी वायु क्षेत्र में समान रूप से हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगाया है, संभवतः अपने सैन्य अभ्यास या हथियार परीक्षण के कारण।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



मोंथा चक्रवात

चर्चा में क्यों ?

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न **चक्रवात** “मोंथा” भारत के पूर्वी तट के निकट पहुँचते ही तीव्र रूप ले रहा है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु

चक्रवात के बारे में:

- परिभाषा: चक्रवात वे तेज वायु-संचलन हैं, जो निम्न-दबाव क्षेत्रों के चारों ओर घूमते हैं, जो उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त घूमता है। ये अक्सर तूफान और गंभीर मौसम उत्पन्न करते हैं।
- चक्रवातों का वर्गीकरण: IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव वाली प्रणालियों को क्षति क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है।
- चक्रवातों का नामकरण: WMO/ESCAP (एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) का ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल, जिसमें 13 उत्तरी हिंद महासागर देश शामिल हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के नामकरण का प्रबंधन करता है।
 - पैनल के पास 13 देशों द्वारा प्रस्तुत नामों की पूर्व-निर्धारित सूची होती है, जिसका क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है।
 - नामों का चयन स्तंभ दर स्तंभ किया जाता है, चाहे चक्रवात कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।

हालिया चक्रवात:

- ‘मोंथा’ नाम, जिसका अर्थ है सुंदर या सुगंधित फूल, थाईलैंड द्वारा दिया गया था।
- इस मौसम के पहले चक्रवाती तूफान का नाम श्रीलंका के सुझाव पर ‘शक्ति’ रखा गया।
- हाल ही में आए अन्य चक्रवातों में शक्ति (श्रीलंका), फेंगल (सऊदी अरब), दाना (कतर), असना (पाकिस्तान) और रेमल (ओमान) शामिल हैं।
- नामकरण सूची के अनुसार, अगला चक्रवात सेंयार (UAE) होगा, उसके बाद दित्वा (यमन), अर्नब (बांग्लादेश) और मुरासु (भारत) होंगे।

DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है।

मुख्य बिंदु

- पारंपरिक रूप से, **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs)** विशेष रूप से माल परिवहन के लिये विकसित किये गए थे, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाना और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ को कम करना था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❖ हालाँकि छठ पूजा (25-28 अक्टूबर, 2025) के दौरान भारी भीड़ के कारण, रेलवे ने पहली बार खाली पैसेंजर कोचिंग रैक और विशेष ट्रेनों को DFC पर चलाने की अनुमति दी।
- ❖ इस कदम से त्योहार के समय अधिक संख्या में पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित करना संभव हुआ।

DFC का स्वरूप:

- ❖ ईस्टर्न DFC (EDFC): ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना (पंजाब) से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए दनकुनी (पश्चिम बंगाल) तक लगभग 1,839 किमी की लंबाई में विस्तृत है। EDFC का अधिकांश वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।
- ❖ वेस्टर्न DFC (WDFC): यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT), मुंबई से दादरी तक लगभग 1,506 किमी लंबा है। WDFC का वित्तपोषण जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा किया जा रहा है।

8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

- ❖ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिये संदर्भ की शर्तों (ToR) को स्वीकृति दे दी है।
- ❖ यह आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना तथा सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा एवं सिफारिश करने के लिये उत्तरदायी है।

मुख्य बिंदु

- ❖ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई थी और इसके संदर्भ की शर्तों (ToR) को 28 अक्टूबर, 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- ❖ आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (रक्षा कार्मिकों सहित) एवं 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
- ❖ आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद संशोधित वेतन एवं पेंशन संरचना जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।
- ❖ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना:

पद	नाम / पदनाम
अध्यक्ष	न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई (पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश)
अंशकालिक सदस्य	प्रो० पुलक घोष (भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरु)
सदस्य सचिव	पंकज जैन (पेट्रोलियम सचिव)

संदर्भ की शर्तें (ToR):

- ❖ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के बाद सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है:
 - ❖ देश की आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय सतर्कता की आवश्यकता।
 - ❖ विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिये संसाधनों की उपलब्धता।
 - ❖ गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अविशेषता लागत (विशेषकर 2004 से पूर्व की पेंशन देयताएँ)।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ❏ राज्य के वित्त पर प्रभाव, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर अपने वेतनमान को केंद्र के अनुरूप करती हैं।
- ❏ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) एवं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक संरचना, लाभ तथा कार्य स्थितियाँ।

❖ पृष्ठभूमि:

- ❏ वेतन आयोग का गठन आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, वेतन संरचना एवं पेंशन में बदलाव की समीक्षा तथा सिफारिश की जा सके।
- ❏ 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वाँ मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है।



मुख्य बिंदु

❖ परिचय:

- ❏ वे 24 नवंबर, 2025 को न्यायमूर्ति बी. आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 10 फरवरी, 2027 तक लगभग 15 माह का कार्यकाल पूरा करेंगे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वह हरियाणा से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
- वह पहली पीढ़ी के वकील हैं, जो अपनी स्पष्ट टिप्पणियों, संतुलित निर्णयों और संवैधानिक नैतिकता पर जोर देने के लिये जाने जाते हैं।
- उनके कार्यकाल में न्यायिक सुलभता, प्रशासनिक सुधार और संवैधानिक व्याख्या में स्थिरता पर विशेष ध्यान दिये जाने की संभावना है।

❖ महत्वपूर्ण निर्णय:

- अनुच्छेद 370: पाँच-सदस्यीय पीठ के सदस्य रहे, जिसने अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा: इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय देने वाली पीठ का हिस्सा रहे।
- चुनाव आयोग की निगरानी: वर्तमान में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की देखरेख करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं।

❖ भारत के मुख्य न्यायाधीश:

- अनुच्छेद 124 (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- वरिष्ठतम न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है (यह परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं)।
- अर्हता: मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को
 - ❑ भारत का नागरिक होना चाहिये,
 - ❑ कम-से-कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या
 - ❑ 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिये,
 - ❑ अथवा राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिये।

- ❖ मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात् ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के भारत के एकीकरण में योगदान के सम्मान में मनाया जाता है।

- ❖ वर्ष 2025 में यह दिवस विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

❖ राष्ट्रीय एकता दिवस:

- यह दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रतिपादित एकता, अखंडता और समावेशिता के मूल्यों का प्रतीक है।
- इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था, जब सरकार ने राष्ट्र-निर्माण में पटेल के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने का निर्णय लिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- वर्ष 2015 के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और परस्पर जुड़ाव को सशक्त करना था।

❖ कार्यक्रम:

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा **माई भारत मंच** के माध्यम से आयोजित **सरदार @150 एकता यात्रा** का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति तथा नागरिक दायित्व की भावना को बढ़ावा देना था, जो 'एक भारत, आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- इसके अतिरिक्त, 31 अक्टूबर, 2025 को देश के प्रमुख शहरों में "रन फॉर यूनिटी" नामक राष्ट्रव्यापी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नई दिल्ली से हुआ।

❖ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी:



- 31 अक्टूबर, 2018 को सरदार पटेल की स्मृति में 182 मीटर (600 फीट) ऊँची विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** का उद्घाटन गुजरात के केवडिया में किया गया।
- यह प्रतिमा **नर्मदा नदी** के तट पर, **सरदार सरोवर बाँध** (जो कंक्रीट की मात्रा के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्व बाँध है) के समीप साधु बेट पहाड़ी पर स्थित है।
- वर्ष 2020 में इसे **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** के "आठ अजूबों" की सूची में भी शामिल किया गया था।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस

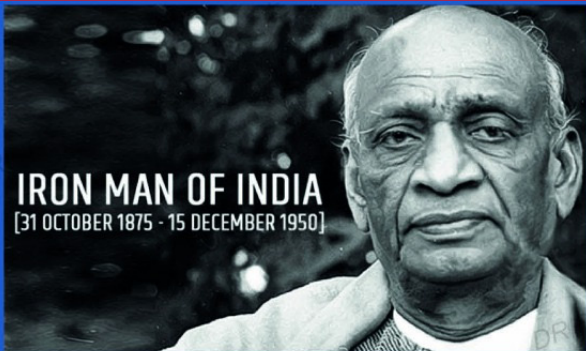


IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप







सरदार वल्लभ भाई पटेल

IRON MAN OF INDIA
[31 OCTOBER 1875 - 15 DECEMBER 1950]

परिचय

- ◆ भारत के पहले गृहमंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री
- ◆ बारदोली की महिलाओं द्वारा 'सरदार' की उपाधि दी गई

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का दृष्टिकोण

- ◆ इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- ◆ इनकी स्मृति में गुजरात में वर्ष 2018 में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया गया।

संविधान सभा की समितियाँ जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की

- ◆ मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति
- ◆ अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर समिति
- ◆ प्रांतीय गठन समिति

प्रमुख योगदान

- ◆ खेड़ा (1918) तथा बारदोली (1928) आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ एकीकृत किया।
- ◆ कांग्रेस के 46 वें अधिवेशन (मार्च 1931) की अध्यक्षता करते हुए गांधी-इरविन समझौते की पुष्टि का आह्वान किया।
- ◆ इन्हें 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की।
- ◆ इन्होंने लगभग 565 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके चलते इन्हें 'भारत का लौह पुरुष' के रूप में जाना गया।

◆ ◆ ◆ ◆

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

